

Discover your divinity with us
A/C Showroom
ज्ञान गंगा ॐ मूर्ति माला केन्द्र
उजाला भवन स्टेशन रोड, दुर्गा
0788-4030383, 3293199
भगवान के वस्त्र, श्रृंगार
मूर्तियां एवं समस्त
पूजन सामग्री
संगमरमर व पीतल की
मूर्तियां राशि रत्न
एवं उपकरण उपलब्ध

राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

समाय



रायपुर एवं दुर्गा से प्रकाशित

दर्शन

संस्थापक : स्व. श्रीमती नलिमा खड़तकर

निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

श्री दुर्गा शहर में
सुप्रसिद्ध
ज्योतिषाचार्य
श्री दुर्गा उपलब्ध मां गुरुगुरु, श्री शारदा, श्री चक्रवर्ती, श्री गणेश जी
अतीव कृपा राधान द्वारा राश्ट्र सरवलाओं का मार्ग दर्शन हेतु
पं. एम.पी. शर्मा/
मो. 8109922001
फीस 251/- मात्र
पता:- श्री दुर्गा ज्योतिष कार्यालय
सिकोला भाठा, सब्जी मार्केट के
सामने, धमधा नाका, दुर्गा

वर्ष 13, अंक 273

पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रूपयें

दुर्गा, गुरुवार 25 जुलाई 2024

www.samaydarshan.in

संक्षिप्त समाचार

जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों के बिना अमरनाथ यात्रा मुमकिन नहीं : उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मॉदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने अब तक बजट नहीं देखा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। नेशनल काँग्रेस नेता अब्दुल्ला ने कहा, हमारी पार्टी पहले बजट को पढ़ेगी। हम देखेंगे कि इस बजट में जम्मू-कश्मीर की बेरोजगारी, बिजली-पानी पर ध्यान दिया गया है या नहीं। अगर बजट निराशाजनक होता है तो हमारी पार्टी को पेश किया गया बजट को संसद में उठाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने 'नेमप्लेट' विवाद पर भी बयान दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था। यदि जम्मू-कश्मीर की बात करें तो यहाँ मुस्लिमों के बिना अमरनाथ यात्रा मुमकिन नहीं है। यहाँ श्रद्धालु, मुस्लिमों के कंधे पर बैठकर अमरनाथ यात्रा करते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को घोड़े पर ले जाने वाले भी मुस्लिम होते हैं। नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों पर होगी कार्रवाई, 25 हजार जुर्माना, 3 साल की जेल

पटियाला। पंजाब सरकार यातायात नियमों को लेकर सख्त रुख अपना चुकी है। अब नाबालिग बच्चे सड़कों पर वाहन लेकर घूमते हुए नजर आए तो उनकी खैर नहीं। पंजाब सरकार ने ऐसे बच्चों के माता-पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। उन्हें 25 हजार तक का जुर्माना और 3 साल कारावास में बिताना पड़ सकता है। एडीजीपी ट्रेफिक एंड रोड सेफ्टी फोर्स की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे यदि दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पत्र के जरिए पंजाब के हर जिले के एसएसपी और कमिश्नर को यातायात नियमों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 31 जुलाई 2024 तक एक अभियान चलाकर बच्चों और अभिभावकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। जागरूकता अभियान में कहा जाएगा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया और चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए।

वित्तमंत्री निर्मला ने बजट को भेदभावपूर्ण बताने पर दिया जवाब...

गलत धारणा फैलाने की कोशिश की जा रही है : निर्मला

नई दिल्ली/ एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट को 'भेदभावपूर्ण' बताने के विपक्ष के दावे पर करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह एक 'अपमानजनक आरोप' है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप विपक्षी दलों की ओर से जानबूझकर लगाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच यह गलत धारणा फैलाई जा सके कि उनके राज्यों को धन या योजनाएं आवंटित नहीं की गईं। वित्त मंत्री ने यह प्रतिक्रिया विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के उस दावे के बाद दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मंगलवार को पेश किया गया बजट देश के राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण है।

राज्य सभा में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष, खासकर एक वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट पर ऐसी बात कही है इसलिए मैं इसका जवाब दे रही हूँ। वित्त मंत्री ने कहा, उन्होंने (खड़गे ने) सवाल खड़ा किया कि मैंने कई राज्यों का बजट में नाम नहीं लिया और केवल दो राज्यों का नाम लिया। मैं यहाँ कुछ बातें कहना चाहूँगी कि भाषण में क्या होता है? कांग्रेस पार्टी इस देश में बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही है और उन्होंने इतने सारे बजट पेश किए हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से पता होगा कि हर बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता है। उन्होंने दावे के बाद दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मंगलवार को पेश किया गया बजट देश के राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण है।



का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वाधवन में बंदरगाह बनाने का फैसला किया है, लेकिन कल बजट में महाराष्ट्र का नाम शामिल नहीं किया गया। क्या इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र को खुद को उपेक्षित महसूस करना चाहिए? वित्त मंत्री ने कहा कि उस परियोजना के लिए महाराष्ट्र के लिए 76 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र का नाम

लेखानुदान में नहीं लिया गया। राज्य के नाम का उल्लेख कल भी नहीं किया गया था; क्या इसका मतलब यह है कि राज्य को अनदेखी की गई? आगे उन्होंने कहा, और मैं इतने सारे अलग-अलग राज्यों का नाम ले सकती हूँ जिनके पास कई प्रमुख परियोजनाएँ हैं। अगर भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत सरकार को योजनाएँ और कार्यक्रम, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, एआईवी आदि से मिलने वाली बाहरी सहायता इन राज्यों में नहीं जाती है? उन्होंने कहा, 'वे नियमित रूप से चलते हैं और सरकार के व्यय विवरण में, सरकार के विभागवार आवंटन में इन सभी बातों का जिक्र होता है। सीतारमण ने कहा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि यह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है ताकि

लोगों के मन में गलत धारणा बने कि उनके राज्यों को धन या योजनाएँ आवंटित नहीं की गईं। कांग्रेस को चुनौती देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती दूँगी कि उन्होंने (कांग्रेस ने) जो भी बजट भाषण दिए हैं, क्या उन्होंने अपने प्रत्येक बजट भाषण में देश के प्रत्येक राज्य का नाम लिया है? यह एक अपमानजनक आरोप है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल पेश किए गए बजट की निंदा की थी और दावा किया था कि आंध्र प्रदेश और बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा था सबके थाली खाली और सिर्फ दो के थाली में पकोड़ा और जलेबी। ये दो स्टेट्स को छोड़कर, किसी को कुछ नहीं मिला। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विमान पोखरा जा रहा था

काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्रैश हुआ विमान, प्लेन में सवार 19 में से 18 की मौत.....

काठमांडू/ एजेंसी

नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह उड़ान भरने के दौरान एक निजी एयरलाइन कंपनी सौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 19 लोग सवार थे। इनमें 18 लोगों की मौत की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विमान पोखरा जा रहा था और सुबह करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवाई अड्डे पर तैनात एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विमान के पायलट को अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि



विमान में लगी आग को बुझा दिया गया है। पुलिस और दमकलकर्मी दुर्घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पोखरा जाने वाले सौर्य एयरलाइंस के विमान के उड़ान भरने के दौरान रनवे से बाहर निकल जाने के कारण यह दुर्घटना

दमकलकर्मी दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान चला रहे हैं। हादसे के बाद काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एहतियातन बंद कर दिया गया है। बीते साल भी नेपाल ने एक विमान हादसे में 72 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2023 में यति एयरलाइंस का विमान नेपाल में हादसे का शिकार हो गया था। यति एयरलाइंस के हादसे में जान गंवाने वालों में पांच भारतीय भी शामिल थे। जांच में पता चला था कि यति एयरलाइंस का हादसा पायलट की गलती से हुआ था, जब विमान के पायलट ने गलती से पावर कट कर दिया था, जिससे विमान हादसे का शिकार हो गया।

संसद में किसान नेताओं से राहुल गांधी ने की मुलाकात

हम एमएसपी की गारंटी के लिए सरकार पर डालेंगे दबाव- राहुल

नई दिल्ली/ एजेंसी

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संसद भवन में किसान नेताओं से मुलाकात की। 12 सदस्यीय किसान नेताओं का प्रतिनिधि मंडल संसद भवन में गांधी के कार्यालय पहुंचा था। कथित तौर पर किसान नेताओं ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए एक निजी विधेयक पेश करने का भी अनुरोध किया। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं ने देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाने

के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया है। हमने आकलन कर लिया है और इसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी हमारी एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि हम डू.ह.डू. गठबंधन के दूसरे नेता से बात करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसान 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। वे नए अपराधिक कानूनों की प्रतियां भी जलाएंगे।

विधानसभा घेरने निकले कांग्रेसी नहीं बढ़ सके आगे

विष्णुदेव साय सरकार नींद में... हम जगाने आए- सचिन पायलट

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध सहित कई मुद्दों को लेकर बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी सड़क पर उतरी। विधानसभा घेराव करने निकले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। इस दौरान पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। इतना ही नहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ को खदेड़ने पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व डिटो



सीएम टीएस सिंहदेव सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे प्रदर्शन को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अभी तो यह झंझोंक ही है पूरी पिछर बाकी है। बलीदाबाजार में एसपी-कलेक्टर ऑफिस जलाए जा रहे हैं। एसपी और कलेक्टर दरवाजे के पीछे छिप रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बरसों से पदस्थ जवान अवसाद में, आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं...

विधानसभा में उठी आवाज...

रायपुर/ संवाददाता

विधानसभा में आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बरसों से पदस्थ पुलिस जवानों की तकलीफों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आवाज उठाई और उनके स्थानांतरण की जरूरत बताई। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी ने कहा कि हमारा बस्तर संभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। पुलिस विभाग के कितने ही जवानों को 10 वर्ष से अधिक समय से यहां पदस्थ करके रखा गया है। ऐसी स्थिति में वे अवसाद में रहते हैं। आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। सरकार ने इनके लिए जो स्थानांतरण नीति बना रखी है आखिर उसका परिपालन कब होगा? उप मुख्यमंत्री (गृह विभाग) विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में पदस्थ उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों व अन्य पुलिस कर्मचारियों को बरबर पदोन्नति दी जाती रही है। यदि कोई 3 साल से ज्यादा का समय गुजार चुका है या आयु 54 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो स्थानांतरण का प्रावधान है, जिसका पालन किया जा रहा है।



सावित्री मंडावी ने कहा कि कुछ लोग पहुंच के बल पर जहां दो-तीन साल में ही बस्तर से बाहर निकल लेते हैं, वहीं कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें 9 से 10 साल हो गए बस्तर में ही डटे रहना पड़ रहा है। पुलिस कर्मियों को आवास उपलब्ध नहीं हो पाता भी बड़ा समस्या है। विजय शर्मा ने कहा कि आवास को लेकर स्थिति वाकई चिंताजनक है। 66 हजार के विरुद्ध 18 हजार आवास ही उपलब्ध हैं। पिछले पांच वर्षों में जब हमारी

सरकार नहीं थी तब 2 हजार ही आवास बने थे। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि ऐसे भी पुलिस कर्मचारी हैं जो 20-22 साल से बस्तर में पदस्थ हैं। उनका स्थानांतरण नहीं हो रहा है। शर्मा ने कहा कि व्यवस्था ऐसी है कि आरक्षक हैं तो इस साल रहेंगे ही। सचन नक्सल क्षेत्र में पदस्थ जवानों को 50 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान है। इस कारण भी बहुत से जवान वहां सेवानिवृत्त होना चाहते हैं।

विष्णुदेव साय सरकार नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार

■ मोर्चे पर असफल बताते कांग्रेस विधायकों ने की नारेबाजी...

रायपुर। संवाददाता

विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि विष्णु देव साय की सरकार नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार है। शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के सवालों का जवाब दे रहे थे। विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने सरकार को नक्सल मोर्चे पर असफल बताते हुए नारेबाजी की प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि गृह मंत्री ने

बड़ी दिलीरी से मेरे ब्यादा पड़े गए सवालों का उत्तर देते हुए बताया है कि पिछले करीब छह महीनों में 273 नक्सली घटनाएँ हुईं। मुठभेड़ में 92 नक्सली मारे गए। 19 जवान शहीद हुए तथा 88 जवान घायल हुए। 34 आम नागरिकों की हत्या हुई। गृह मंत्री बताएं कि जिन 34 आम नागरिकों की हत्या हुई वह कैसे हुई? गोली लगने से हुई, गला काटकर की गई या अन्य तरीके से की गई? मंत्री विजय शर्मा ने जवाब में कहा कि नक्सलियों ने 4 लोगों को जन अदालत लगाकर मार डाला। नक्सलियों द्वारा आईडी बिछाकर रखा गया था उसमें कुछ निर्दोष नागरिक मारे गए। मुखबिरी के शक में 24 लोगों को मार डाला गया। फयरिंग में 1 व्यक्ति की मौत हुई। डॉ.



महंत ने पूछा कि गिरफ्तार किए गए 401 नक्सलियों में कितने इनामी नक्सली हैं, इनमें से कितने छत्तीसगढ़ के हैं और कितने बाहर के हैं? मंत्री ने पहले इनामी नक्सलियों का विवरण दिया फिर कहा कि कितने बाहर के हैं और कितने



छत्तीसगढ़ के कोई श्रेणी तैयार करने नहीं रखी गई है। डॉ. महंत ने कहा कि बार-बार यही बताया जाता है कि नक्सलियों की भरमार बंदूकें जप्त हुईं। ये भरमार बंदूकें चलती हैं या नहीं, क्या इसकी जांच कराई गई है? आज की तारीख में

क्या किसी ने भरमार बंदूकों को चलते देखा है? मेरे पास जानकारी आई है कि पुलिस वाले भरमार बंदूकें लेकर जाते हैं और उसे नक्सलियों की लाश के पास रख देते हैं। शर्मा ने कहा कि इस तरह का प्रस्तुतिकरण होते देख अजीब लग रहा है। पांच एके 47 हथियार बरामद हुए हैं। लांच बरामद हुए हैं। इसके अलावा और भी आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। डॉ. महंत ने कहा कि अविभाजित मध्यप्रदेश के समय में 1995 में मैं भी प्रदेश सरकार में गृह मंत्री रहा था। उस जमाने में भरमार बंदूकें नहीं होती थीं। शर्मा ने कहा कि भरमार बंदूकों के अलावा और भी हथियार बरामद होते रहे हैं। उन पर भी गौर करें। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी

ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि बीजापुर जिले के पीडिया ग्राम में 600 जवान ऑपरेशन में निकले होते हैं, जिनके साथ मुठभेड़ में 11 लोग मारे जाते हैं। मृत लोगों के पास से 10 भरमार प्रस्तुतिकरण होते देख अजीब लग रहा है। 11 में से 10 ग्रामीण थे जिन्हें नक्सली बताकर मार डाला गया। गृह मंत्री ने कहा कि आपकी भी तो सरकार रही, आपने क्या किया? विक्रम मंडावी ने कहा कि हम दावे नहीं करते थे। आप तो दावे करते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि जहां तक पीडिया में हुई घटना की बातें हैं तो मारे गए लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है। डॉ. महंत ने कहा कि मैं आपको सराहना करता हूँ। आपने गौर करें। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी

विजय शर्मा ने कहा कि वह विष्णुदेव साय की सरकार उनसे बात करने को तैयार है। डॉ. महंत ने कहा कि यह बात आप छह से 7 महीने से कहते आ रहे हैं। इस दिशा में कौन सी कोशिशें हुईं? बात करने के लिए एक मीडियेटर ढूंढना पड़ता है। कुछ तो किया होगा आपने। कांग्रेस विधायक कवामी लखमा ने कहा कि पीडिया में तेंदूपता तोड़ने के लिए जमा हो रहे थे, विक्रम मंडावी ने कहा कि हम दावे नहीं करते थे। आप तो दावे करते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि जहां तक पीडिया में हुई घटना की बातें हैं तो मारे गए लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है। डॉ. महंत ने कहा कि मैं आपको सराहना करता हूँ। आपने गौर करें। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी

संक्षिप्त समाचार

तहसील कार्यकारिणी की बैठक 26 जुलाई को होगी, तहसील स्तरीय तीज महोत्सव की बनेगी रूपरेखा



तहसील साहू संघ पाटन की कार्यकारिणी बैठक 26.07.2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 12.00 बजे से साहू सदन पाटन में आयोजित की गई है जिसमें विभिन्न विषयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा किया जाएगा छ बैठक में प्रमुखतः तहसील स्तरीय कर्मा जयंती एवं सामूहिक आदर्श विवाह 2024 आय-व्यय की जानकारी, सत्र 2023-2024 आमसभा की तैयारी पर चर्चा, तीज मिलन समारोह के आयोजन पर चर्चा, आगामी तहसील स्तरीय कर्मा जयंती महोत्सव एवं विशाल आदर्श विवाह के आयोजन पर चर्चा, आमसभा में सुझाव पत्र आर्म्बित करने बाबत स्थानीय / परिक्षेत्र / तहसील साहू संघ द्वारा के विषय पर चर्चा, सामूहिक आदर्श विवाह एवं विशाल कर्मा जयंती ग्राम पतौरा के लिए निर्धारित दान राशि अप्राप्त ग्रामीण इकाई पर निर्णय, अध्यक्ष के अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा किया जाएगा छ बैठक में तहसील साहू संघ पाटन के समस्त पदाधिकारी सहित समस्त प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक, कार्यकारिणी सदस्य गण, पांचों परिक्षेत्र के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, निन्यानबे इकाई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की उपस्थिति रहेगी छ उक्त जानकारी खेमलाल साहू महासचिव तहसील साहू संघ पाटन ने दिया है छ

2024 बजट में है सबका साथ सबका विकास-प्रखर



सरायपाली (समय दर्शन)। बजट 2024 ने आम आदमी के साथ साथ सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ विशेष है बजट में मुख्यतः कृषि, बेरोजगारी, ग्रामीण एवं शहरी विकास के साथ आने वाली पीढ़ी का भी विशेष ध्यान रख कर बजट तैयार किया गया है देश की मोदी सरकार 5 विभिन्न योजनाओं के जरिये देश के युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है जिसका सीधा लाभ देश के 4 चार करोड़ युवाओं को मिलेगा वहीं दूसरी ओर देश के 1 करोड़ युवाओं को देश की शोष 500 कम्पनियों में इंटरशिप की योजना है जिसमें प्रति माह 5000 रुपए दिये जाएंगे, वहीं प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आर्बित किए गए हैं जिससे शहरी क्षेत्र में एक करोड़ मकान एवं ग्रामीण क्षेत्र में दो करोड़ मकान बनाए जाएंगे, किसानों के लिए बजट में अलग से 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपए आर्बित किया गया है वहीं अगले दो साल में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि में योग्य बनाने का लक्ष्य देश की मोदी सरकार ने रखा है, वहीं ग्रामीण विकास के लिए अलग से इस बार 2 लाख 66 हजार करोड़ आर्बित किए गए हैं जिसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, महिलाओं के योजनाओं के लिए बजट में तीन लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं जिससे महिला सशक्तिकरण योजनाओं के लिए कार्य किया जा सकेगा, छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री मुद्रा लोन योजना में पहले जो 10 लाख दिए जाते थे उसे बढ़ा कर 20 लाख कर दिया गया है वहीं आत्म निर्भर भारत की सार्थकता बनाए रखने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए देश की मोदी सरकार ने बजट में से सबसे ज्यादा हिस्सा लगभग 13 प्रतिशत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए देश की सुरक्षा क्षेत्र के लिए आर्बित किया है जिससे देश की सेना को और भी अधिक मजबूत ताकतवर बनाया जा सकेगा, बजट में छात्रों के लिये शिक्षा ऋण, देश के विनिर्माण जैसे अन्य कार्यों के लिए ध्यान रख कर देश के सर्वांगीण विकास के लिए देश की मोदी सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है

25 जुलाई को ग्राम पंचायत केस में आयोजित होगा जनसमस्या निवारण शिविर

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के निर्देशन में जिले में आम ग्रामीणजनों की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं शिकायतों के समाधान आसानी हो सके इसके लिए 26 दिसंबर 2024 तक जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जनसमस्या निवारण शिविर में जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीण जनों के समस्याओं का निराकरण करेंगे।

खारुन नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट

एसडीएम ने नदी किनारे गांवों में जाकर स्थिति का लिया जायजा, खारुन नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी

पाटन (समय दर्शन)। पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पाटन क्षेत्र के जीवन दायिनी कहे जाने वाली खारुन नदी ऊफन पर है। यहां पर जितने भी एनीकेट है उनके ऊपर से पानी बह रही है। वहीं नदी किनारे के गांव में पानी काफी करीब भी पहुंच चुके हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। एसडीएम पाटन दीपक कुमार निकुंज ने निरीक्षण करके जितने भी नदी किनारे के गांव हैं वहां पर



सचिव एवं कोटवार को अलर्ट रहने निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जितने भी सामुदायिक भवन है उसे भी खाली रखने के लिए कहा गया है जिससे की बाढ़ की स्थिति में वहां पर लोगों को ठहराया जा सके। बहरहाल अभी स्थिति ठीक है कहीं भी गांव के अंदर पानी पहुंचाने की जानकारी नहीं है।

पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण खारुन नदी अभी ऊफन पर है यहां पर निपानी, किकिरमेटा, केसरा, बोरिंदा तारीघाट सोनपुर ठाकुरान तोला सहित अन्य गांव में पानी काफी बढ़ रही है धीरे-धीरे खारुन नदी में भी पानी का बहाव तेज हो रहा है। सभी एनीकेट के ऊपर से बह रहा पानी- खारु नदी के विभिन्न गांव में

एनीकेट बनाए गए हैं। इन सभी एनिकेट के ऊपर से पानी बह रहा है। किकिरमेटा से लेकर अमलेश्वर तक के सभी गांव में लगभग एनीकेट बने हुए हैं इन एनीकेट में कम से कम 5 से 10 फीट ऊपर पानी बह रहा है। जिससे की रास्ता को बंद कर दिया गया है। बाढ़ से निपटने तैयारी पूरी- खारु नदी में पानी को बढ़ाते देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पहले से ही पूरी कर ली है। एसडीएम पाटन दीपक कुमार निकुंज ने खारुन नदी के किनारे स्थित सभी गांव के सचिव एवं कोटवारों को निर्देश दिया गया है कि वह लगातार कानून के जलस्तर पर नजर रखें। कहीं पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाए तो वहां पर किसी को जाने न देवे।

नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन हेतु चलाया जा रहा जागरूकता अभियान

जांजगीर-चांपा (समय दर्शन)। कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन 2024 "नारी शक्ति से जल शक्ति" थीम के साथ जिले में चलाया जा रहा है। जिसमें जल संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। नारी शक्ति के द्वारा विभिन्न अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में पौध रोपण, जल संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं। इसके तहत बरसात का पानी बर्बाद होने से रोकना, भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाना, हैंडपंप, कुएं और तालाब के पानी संरक्षित करना है।



पंचायत बोरसी में ग्रामीणों स्वसहायता समूह की महिलाओं ने इस अभियान के तहत पौध रोपण किया और जल संरक्षण की शपथ भी ली। इसके साथ ही महिलाओं ने गांव में रैली निकालकर जल संरक्षण को बढ़ावा देते हुए जनजागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से गांव में पौध रोपण, तालाब, डबरी, कुआं, चेक डेम, रेन हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

आम जन हितैषी बजट, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है : बिशेसर दास

राजनांदगांव (समय दर्शन)। वरिष्ठ भाजपा नेता, नवाचारी कृषक एवं सांसद प्रतिनिधि बिशेसर दास साहू ने मंगलवार को जारी केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा है कि यह बजट आम जनता का हितैषी बजट है जिसमें मोदी सरकार ने सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा है। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बिशेसर दास साहू ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वह सर्वोन्मुखी है। कृषि कार्य के लिए 152 लाख करोड़ रुपए, महिलाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, 3 करोड़ करोड़ बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर नौकरी दिया जाएगा, यह अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। कौशल विकास में प्रशिक्षित लोगों के लिए मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़कर 20 लाख किया



गया है इससे सभी लोगों को रोजगार मिलेगा और वह अपने स्तर पर अन्य लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे। कृषि विकास में दलहन और तिलहन को फोकस किया गया है, किसानों को बिजली मुफ्त देने के लिए सौर ऊर्जा से बिजली के कनेक्शन हेतु विशेष छूट का प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा लाभ किसान उठाएंगे और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। बिशेसर दास साहू ने आगे कहा कि कैंसर को दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्स-रे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीपहूस का सस्ता किया जाना इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार की सोच कितनी दूरदर्शी है। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर, ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किशतों में मिलेगी, जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। बिशेसर ने कहा कि किसानों का विशेष ख्याल रखते हुए 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 रजनों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बिशेसर दास साहू ने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट देश के विकास को और ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट है।

विधायक चातुरी नंद ने खाद की कमी और बिजली कटौती के मुद्दे पर विधानसभा में रखी अपनी बात

सरायपाली (समय दर्शन)। सरायपाली विधायक चातुरी नंद ने क्षेत्र में खाद की कमी के चलते किसानों को हो रही परेशानियों और अघोषित बिजली कटौती के मुद्दे पर विधानसभा में अपनी बात रखी। विधानसभा में कार्यवाही के दौरान विधायक चातुरी नंद ने कहा कि एक तरफ सरकार दावा करती है कि खाद की कमी नहीं है वहीं दूसरी तरफ किसान खाद की कमी के चलते खेती किसानों छोड़ सोसायटी के चक्कर काटने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि किसानों को डीएपी नहीं दी जा रही और उसके बदले दूसरे खाद थमा दिए जा रहे हैं। सोसायटी में डीएपी नहीं मिल रहा हा लेकिन प्राइवेट खाद दुकानों में कोई कमी नहीं है। विधायक नंद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को मोदी की गारंटी देने वाली सरकार आज किसानों को खाद बीज तक नहीं दे पा रही है (उन्होंने अमानक बीज के मुद्दे को भी कृषि मंत्री के समक्ष रखा। विधायक नंद ने विधानसभा में कहा कि क्षेत्र में



अघोषित बिजली कटौती की जा रही है जिससे क्षेत्रवासी परेशान है। उन्होंने ग्राम मोहनमुंडा में 15 दिनों से बिजली बंद का मुद्दा भी मंत्री जी के समक्ष रखा। बता दें कि सरायपाली विधायक चातुरी नंद विधानसभा में अपने बेबाक अंदाज और तेजतर्रार वक्ता के रूप में जानी जाती हैं। मानसून सत्र में भी उनका वही अंदाज देखने को मिल रहा है।

अतिवृष्टि भारी वर्षा से चिखली स्थित मकान क्षतिग्रस्त, मकान मालिक व उनकी पत्नी बाल-बाल बचे

राजनांदगांव (समय दर्शन)। 20 जुलाई, 2024 को हुए अतिवृष्टि भारी वर्षा से मेरे मकान के दोनों कमरे व बरामदे में पानी भर गया। हेमंत साहू व उसकी पत्नी अर्चना साहू साथ मिलकर कमरे से पानी बह फेंक रहे थे, तभी अचानक ऊपर मकान का कवेलू टूटकर पटाव के साथ किचन स्टोर (कमरे) में गिरा गया, जहां वे दोनों कमरे में भरे पानी फेंक रहे थे। दोनों भगवान महाकाल की दया-दृष्टि से बाल-बाल बच गए। भारी वर्षा से उक्त मकान के टूटकर गिरने से खाद्य सामग्री बर्तन व महंगे वस्त्र की छत्ती हुई, जिससे सिर्फ आर्थिक छ्ती हुई, भगवान महाकाल की दया दृष्टि से चिखली निवास हेमंत साहू व उनकी पत्नी की जान बची। हेमंत साहू ने बताया कि उक्त संबंध में दुर्घटना से पूर्व भी अपनी दोनों बहन लता साहू एवं सविता साहू को व साथ ही अपने परिवार के चाचा व बुआ, दीदी को एवं साथ ही कई बार मुहल्ले के बुजुर्ग व संबंधियों को ले जाकर चर्चा कर चुका था कि मकान जर्जर हो चुका है, इस 2 कमरे के जर्जर



मकान को बनाना अनिवार्य है, जो लोन के माध्यम से ही संभव है, चूंकि 2 कमरे का 3 भाई बहनों में नही बांटा जा सकता, इसके लिए मकान का हकत्याग करना आवश्यक है। हकत्याग के एवज में दोनों बहनों के नाम से 25-25 हजार देने व हकत्याग रजिस्ट्री खर्च स्वयं वहन करने को तैयार था। वर्तमान में एक बहन का निधन हो चुका है, उनके 3 बेटियां हैं जिनका विवाह हो चुका है, इन तीनों भांजी-दामाद से भी उक्त संबंध में चर्चा कर चुका है, पर पहले एक बहन लता, सविता पर हां-हां कहकर टालती रही, अब भांजी-दामाद अपनी मौसी लता पर टाल रहे हैं, जिसका आज ये दुष्परिणाम हुआ कि अतिवृष्टि भारी बारिश से मकान क्षतिग्रस्त हो गया और हम दोनों पति-पत्नी भगवान महाकाल के आशीर्वाद से जीवित है।

बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद की जयंती, बिसाहू दास महंत की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने किया नमन

राजनांदगांव (समय दर्शन)। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में 23 जुलाई, मंगलवार को स्थानीय कांग्रेस भवन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं. बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती व छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्ट व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. बिसाहू दास जी महंत की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी सभा आयोजित की गई। इससे पूर्व उपस्थित कांग्रेसजनों ने तीनों महान विभूतियों के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि अर्पित की। संगोष्ठी सभा का संचालन शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अमित चंद्रवंशी ने किया।



अहम भूमिका निभाई है। महान उपलब्धियां कभी आसानी से नहीं मिलती। अध्यक्ष श्री छाबड़ा ने शहीद बाल गंगाधर तिलक के योगदानों को याद करते हुए कहा कि सामाजिक स्वप्नदृष्ट के साथ एक शिक्षक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर से बंधी हुई थी, कांग्रेस और गांधीजी के विचारधारा में चलते हुए इन आदर्श महापुरुष ने अपना बलिदान देकर देश को आजाद कराया था। युवाओं के मार्गदर्शक हैं चंद्रशेखर आजाद देश की आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, शहीद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि आजाद हूँ और आजाद मरूंगा। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्ट व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. बिसाहू दास जी हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, हम हमेशा इनका स्मरण करते रहे और उनके बलिदान को आने वाली पीढ़ी को

बताएं। देश के विकास में कांग्रेस का अहम योगदान है, कांग्रेस ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने त्याग और तपस्या की मूर्ति हमारे देश के क्रांतिकारी धरोहरों के जीवन पर संगोष्ठी सभा आयोजित की जाती है। संगोष्ठी सभा को उतर ब्लॉक अध्यक्ष आसिफ अली ने भी संबोधित किया। इस दौरान प्रमुख रूप से संभागीय प्रवक्ता कमलजीत सिंह पिन्टू, रमेश डाकलिया, मन्ना यादव, शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष मोहम्मद यहया, दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष सूर्यकांत जैन, बबलू कसार, पार्षद सिद्धार्थ डोंगरे, दुलारी साहू, पूर्णिमा नागदेवे, मोहिनी सिन्हा, प्रज्ञा गुप्ता, युवक कांग्रेस अध्यक्ष गुरभेज माखिजा, शैलेश ठावरे, देवेन्द्र साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजनों उपस्थित थे। संगोष्ठी सभा में उपस्थित कांग्रेसजनों का आभार प्रदर्शन शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस श्रीमती शारदा तिवारी ने किया। तत्पश्चात कांग्रेसजनों द्वारा दो मिमट की मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। संगोष्ठी पश्चात उपस्थित कांग्रेसजनों ने गुरुद्वारा के पास स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद व अन्य शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इसके बाद भरकापारा इंदिरा सरोवर स्थित शहीद बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा में माल्यार्पण कर जयघोष के नारे लगाए।

सार समाचार

न्यायालय के गेट के पास खड़ी बाइक पार

रायपुर (समय दर्शन)। पंडरी रोड न्यायालय गेट नंबर 3 के पास खड़ी बाइक को अज्ञात चोर ने पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सैयद अनवर अली 30 वर्ष लक्ष्मीनगर मोवा का रहने वाला है। बताया जाता है कि प्रार्थी अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 केजे 4489 को पंडरी रोड स्थित न्यायालय के गेट नंबर 3 के पास खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 10 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

सरेआम शराब पीते आठ पकड़ाए

रायपुर (समय दर्शन)। राजधानी पुलिस ने नशेइंद्रियों के खिलाफ अभियान चलाकर सरेआम शराब पीते 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया है। मिली जानकारी के अनुसार खम्हारडीह पुलिस के कचन रोड में सरेआम शराब पीते आरोपी विनय श्रीवास्तव 32 वर्ष, आशीष सिंह 34 वर्ष व खोमान साहू 33 वर्ष को गिरफ्तार किया है। वहीं खमतवाड़ी पुलिस ने आरोपी चंद्रदेव पण्डित 52 वर्ष, पवन साव 36 वर्ष व ओमनारायण साहू 29 वर्ष को गिरफ्तार किया है। इसी तरह मोवा पुलिस ने आरोपी नागेंद्र नेताम 27 वर्ष व आरंग पुलिस ने आरोपी योगेश कोसले 19 वर्ष को गिरफ्तार किया है।

महिलाओं के लिए निराशाजनक बजट वंदना राजपूत

रायपुर (समय दर्शन)। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि बजट से महिलाओं को हर बार की तरह इस बार भी बजट में निराशा हाथ लगी। महिलाओं को बजट से बहुत ही उम्मीद थी कि एक महिला वित्त मंत्री है जो महिलाओं की परेशानी को समझ कर बजट पेश करेगी लेकिन यह अनुमान हर बार की तरह इस बार भी गलत निकला। इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं। महिलाओं को लग रहा था कि खाने-पीने की वस्तुओं में पहली बार यदि कोई सरकार जीएसटी लगाया था तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो खाद्य पदार्थ पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाए थे जिसके कारण खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। महिलाओं के रसोई में संकट छाया हुआ है। आज गरीब के थाली से दाल गायब हो रही है। सब्जी गायब हो रहा है।

जूनियर कॉमनवेल्थ गेम्स न्यूजीलैंड में दिलाया रजत पदक, रायपुर की कुमार रीबा बेन्नी और बिलासपुर की कुमारी रूपाली साहू ने न्यूजीलैंड में लहराया भारत का परचम

छत्तीसगढ़ की बेटियों ने राज्य और देश का मान बढ़ाया - खेल मंत्री टंक राम वर्मा

रायपुर (समय दर्शन)। खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा के निवास कार्यालय में आज तलवारबाजी खिलाड़ी रूपाली साहू ने सौजन्य मुलाकात की। रूपाली साहू और रीबा बेन्नी ने 12 से 19 जुलाई, 2024 तक क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में सम्पन्न जूनियर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारतीय टीम को सिल्वर पदक दिलाया। खेल मंत्री ने इनके शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटियों ने राज्य का ही नहीं अपितु देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी खेल विधाओं के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। खेल मैदानों को उन्नत कर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जात हो कि रूपाली साहू और रीबा बेन्नी ने न्यूजीलैंड जाने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग से आर्थिक मदद



के लिए आवेदन किया था। खेल संचालक श्रीमती तनुजा सलाम ने इन खिलाड़ियों रिबा बेन्नी को 4 लाख रुपए और रूपाली साहू को 3.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण राज्य शासन को प्रेषित किया था। खेल

संचालक के प्रस्ताव पर खेल सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता और खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने स्वीकृति प्रदान की। इन खिलाड़ियों ने तलवारबाजी में बेहतर प्रदर्शन के लिए बहुत परिश्रम किया है। अपने बेहतर प्रदर्शन और खेल तकनीक की योग्यता के कारण

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मैडल प्राप्त करने में सफल रहें। खेल संचालक श्रीमती तनुजा सलाम ने इन खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

बजट में बिहार-आन्ध्र जैसी बैसाखियों के लिये विशेष प्रावधान, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा : दीपक बैज

रायपुर (समय दर्शन)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार का बजट देश की जनता को निराश करने वाला है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था का बर्बाद करने वाला है। बजट में निम्न, मध्यम वर्ग पर भार डाला गया है। पुराने टैक्स रिजिम में पिछले 10 वर्षों से आयकर छुट की सीमा वही की वही है, इस बार भी नहीं बढ़ा। 80 सी और 80 डी की लिमिट भी यथावत है। मकान के लिए ऋण की छुट भी नहीं बढ़ी। यदि 50 हजार रु. भी मंदिना कमा रहे है तो 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। नये टैक्स स्लेब के अनुसार लगभग पूरे निम्न, मध्यम



आय वर्ग से कर वसूला जायेगा। मोदी का चुनाव में वादा 4 करोड़ मकान बनाने का था लेकिन बजट में सिर्फ 1 करोड़ मकान के लिये प्रावधान किया है। जनता को ठगने का काम शुरू हो गया। महंगाई से बैसाखियों बिहार और आन्ध्रप्रदेश के लिये विशेष

प्रावधान किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल राज्य की उपेक्षा की गयी है। छत्तीसगढ़ की उपेक्षा एक बार फिर से जाहिर हो गया है, कि भाजपा के लिये छत्तीसगढ़ का विकास कोई मायने नहीं रखता। चुनाव में डबल इंजन की सरकार के फायदे बता कर वोट लिया था। बजट में डबल इंजन की सरकार ने छत्तीसगढ़ से धोखा किया। रायपुर से राजनांदगांव होकर हैदराबाद एक्सप्रेस वे, जो 2022 में घोषित किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है इस बजट में कोई नया राजमार्ग छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है।

रायपुर (समय दर्शन)। केंद्रीय बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बजट की विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे देश सहित प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और रोजगार के

केंद्रीय बजट विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी - उपमुख्यमंत्री शर्मा

रायपुर (समय दर्शन)। केंद्रीय बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बजट की विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे देश सहित प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और रोजगार के



क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। 5 साल में 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरशिप, स्किल इंडिया के तहत युवाओं को प्रशिक्षित और पुनर्प्रशिक्षित करने

के कदम से देश में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन देने के लिए उदाए गए कदम से देश तकनीकी क्षेत्र में उन्नत बनेगा। उन्होंने कहा कि शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए गए कोष से नई खोजों और आविष्कारों को बल मिलेगा। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान युवा पर बजट में फोकस किया गया है।

केंद्र के बजट में विकसित भारत 2047 की झलक : रामविचार नेताम



रायपुर (समय दर्शन)। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 की झलक है। यह बजट गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की सशक्तिकरण पर केंद्रित है। नेताम ने विकसित भारत की लक्ष्य को लेकर पेश की गई बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सबको अवसर के सिद्धांत पर आधारित इस बजट में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। नेताम ने कहा कि किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस फंड से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों से जुड़े उत्पादन संगठनों, कोऑपरेटिव और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात कही गई है। जो एक सराहनीय पहल है। मंत्री नेताम ने कहा कि बजट में जनजातियों के विकास के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत सरकार जनजातीय इलाकों का विकास करेगी। इसके तहत 63 हजार गांवों का विकास होगा।

रायपुर (समय दर्शन)। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 की झलक है। यह बजट गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की सशक्तिकरण पर केंद्रित है। नेताम ने विकसित भारत की लक्ष्य को लेकर पेश की गई बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सबको अवसर के सिद्धांत पर आधारित इस बजट में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। नेताम ने कहा कि किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस फंड से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों से जुड़े उत्पादन संगठनों, कोऑपरेटिव और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात कही गई है। जो एक सराहनीय पहल है। मंत्री नेताम ने कहा कि बजट में जनजातियों के विकास के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत सरकार जनजातीय इलाकों का विकास करेगी। इसके तहत 63 हजार गांवों का विकास होगा।

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और अन्य ने नई दिल्ली में बजट सत्र के दौरान संसद भवन में विरोध प्रदर्शन किया।



युवक को बंधक बनाकर पीटा, पुलिसने निकाला बदमाशों का जुलूस

रायपुर (समय दर्शन)। पुलिस ने युवक को बंधक बनाकर अपहरण और मारपीट करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद चारों बदमाशों का मुंडन कर पुलिस ने जुलूस निकाला। दरअसल 15 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे शंकर सिंह ठाकुर उर्फ पन्ना को बुद्ध चौक चौकी, राम नगर के पास से घर के अंदर बंधक बनाकर आरोपी प्रिंस बागडे, अंकुश रहंगडाले और उनके साथियों ने बेसबाल बैट और चाकू से मारपीट की थी। इस हमले में शंकर सिंह को गंभीर चोटें आई थीं। घटना के बाद थाना गुडियारी में अपराध क्रमांक 483/24, धारा 140(2), 127(2), 109, 3(2) ब्रह्म के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। घटना के बाद आरोपी लगातार स्थान बदलकर पुलिस से छिपने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने आरोपीयों की तलाश के लिए तीन टीमों बनाई थीं। ये टीमों आपसी सामंजस्य से आरोपियों को पता नहीं कर पाई। आरोपी उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, कन्नौज और जबलपुर समेत कई स्थानों से भागते रहे। पुलिस ने घेराबंदी कर अंततः आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

माता-पिता के सपनों को गढ़ने अच्छी शिक्षा पा रहे सेमरहा के बच्चे : मुख्यमंत्री

विधानसभा में मुख्यमंत्री से मिले बाह्यानी हादसे में मृत तेंदूपता संग्रहकों के बच्चे

रायपुर (समय दर्शन)। कवर्धा जिले के ग्राम बाह्यानी में हुए एक हादसे में तेंदूपता संग्रहण करने गये 19 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई थी। इनके पीछे छूट गये थे इनके मासूम बच्चे। इनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर इनके माता-पिता का कितना कुछ सपना था, जिन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी थी। घटना के तुरंत पश्चात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई थी। साथ ही विधायक भावना बोहरा ने इन मासूम बच्चों के परिवार की जिम्मेदारी ली। सुखद बात यह है कि यह बच्चे



अपनी तरक्की की राह में तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में इन बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को खूब दुलारा और कहा कि आप लोगों ने विधानसभा देखी है।

यहां पर हम सब चर्चा करते हैं और सब मिलजुलकर प्रदेश के विकास के लिए नीति तैयार करते हैं। कल जब आप लोग भी बड़े होंगे। और आप में से जो जनप्रतिनिधि बनेगा वो यहां आएंगे। यह लोकतंत्र का मंदिर

है यहीं से हम प्रदेश के विकास की राह तैयार करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी को विधानसभा दिखाने के पीछे हमारी मंशा यह है कि बच्चे बेहतर तरीके से समझें कि लोकतंत्र कैसे काम करता

है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा। बच्चों ने कहा कि उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनके गांव के बारे में भी पूछा। बच्चों ने अपने गांव के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से

बजट से सभी वर्ग छले गए : सुशील

रायपुर (समय दर्शन)। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के बजट से गरीब, युवा किसान, मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा, महिला सभी छले गये हैं, इस बजट में रोजगार के लिये, कृषि के लिये, लघु उद्योगों के लिये कुछ भी नहीं है। बजट में सुदृढ़ भारत का रोड मैप कहीं भी नहीं दिख रहा है बजट में महंगाई कम करने के बारे में वित्तमंत्री ने कोई प्रावधान नहीं किया है। गरीब, मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत नहीं मिला है उल्टे इस बजट में निम्न मध्यम वर्ग को भी आयाकर के दायरे में ला दिया गया है। बजट देने के लिये जनता से वसूलने के लिये बनाया गया है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस सरकार में रोजगार है नहीं और ईपीएफओ के प्रोत्साहन का झांसा दिया जा रहा है, वित्तीय घाटा लगातार बढ़ रहा है 14 लाख करोड़ का नया कर्ज देश को गर्त में डूबने वाला है महंगाई में राहत नहीं, गैस सप्लिडी, डीजल में 10 गुना बढ़ाए गए सेंट्रल एक्ससाइज में रियायत का कोई जिक्र नहीं छत्तीसगढ़ की उपेक्षा एक बार फिर से जाहिर हो गया है, रायपुर से राजनांदगांव होकर हैदराबाद एक्सप्रेस वे, जो 2022 में घोषित किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है इस बजट में कोई नया राजमार्ग छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि रायपुर से बलौदा बाजार होकर रायगढ़ जाने वाली रेल लाइन की घोषणा लगभग 8 साल पहले हुई थी एक नया पैसा इस मद में केंद्र की मोदी सरकार ने नहीं दिया है नया रायपुर में एम्स की घोषणा 4 साल पहले की गई थी राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण करके केंद्र को सौंप दिया है लेकिन उसे मत में भी एक नया पैसा केंद्र की मोदी सरकार ने स्वीकृत नहीं किया है। कृषि उत्पादन, हथकरघा और कपड़ा के एक्सपोर्ट के लिए कोई कार्ययोजना नहीं है।

जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने विधायक श्रीमती बोहरा को कहा कि बच्चों को इतनी सुंदर शिक्षा आप दे रही हैं। यह बहुत अच्छी बात है। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में हम जितना काम करेंगे, हमारे विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। गौरतलब है कि विगत 20 मई 2024 को कवर्धा जिले के ग्राम बाह्यानी के समीप एक दुखद सड़क दुर्घटना में तेंदूपता तोड़कर लौट रहे 19 ग्रामीणों की दुःखद मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री ने हादसे में तत्काल परिजनों को राहत देते हुए 5-5 लाख दिए जाने की घोषणा की थी। आज इन्हीं मृतकों परिवारों के 14 बच्चे मुख्यमंत्री से मिलने विधानसभा पहुंचे थे।

संपादकीय



रेल की यात्रा डरावनी

एक बार फिर रेल हादसे ने देशभर में यात्रियों के लिए चिंता पैदा की है। उत्तर प्रदेश के गाँवां में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 15 बोगियाँ बेपटरी हो जाने की घटना में वैसे तो 3 यात्रियों की जान गई, मगर इसने रेलवे की व्यवस्था में व्याप्त कमियों और लापरवाहियों को जरूर जिंदा कर दिया है। हालाँकि, हादसा मानवीय भूल की वजह से हुआ है या इसके पीछे कोई साजिश है—जैसा कि इंजन के ड्राइवर ने कहा कि हादसे के पहले जोर का विस्फोट हुआ था—यह तो जांच के बाद ही मालूम चल पाएगी, किंतु हाल के वर्षों में रेल की यात्रा थोड़ी डरावनी जरूर हो गई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें 9 यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। देश में पहले भी रेल हादसे हुए हैं और कइयों की जान गई है, मगर हाल के वर्षों में दुर्घटना का स्वरूप बदल गया है। निसंदेह मोदी सरकार के 10 वर्षों के दौरान रेलवे ने तरक्की की नई इबारत लिखी है, किंतु कई मामलों में अब भी रेल महकमे में सुधार की जरूरत है। खासकर संरक्षा और सुरक्षा के मामले पर सरकार को ज्यादा गंभीर और संवेदनशील होना पड़ेगा। स्वचालित सिगनालिंग प्रणाली भी सवालों के घेरे में है। इसके अलावा पायलट और लोको पायलटों को मिलाने वाली सुविधा अप्रत्याशित है। उन्हें आराम नहीं मिल पाता है और इंजन में भी उनके लिए सामान्य सुविधा तक की कमी दिखती है। इसी तरह संचालन प्रबंधन में कई तरह की खामियाँ और कमी के अलावा महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों की कमी और कबच प्रणाली को लागू नहीं करने के फैसले से मुंह नहीं चुराया जा सकता है। वैसे भी जब ऐसे हादसे होते हैं तो इसका खामियाजा यात्रियों की जान जाने के अलावा रेलवे की संपत्ति को हुए नुकसान से भी जोड़कर देखने की जरूरत है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेल में संरक्षा श्रेणी के स्वीकृत कुल करीब 10 लाख पदों में से डेढ़ लाख से अधिक पद खाली हैं। हालाँकि रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में इस मामले में महत्वपूर्ण निवेश करने के साथ कई संरचनात्मक और प्रणालीगत सुधार भी किए हैं, जिनका सुरक्षित परिचालन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके बावजूद अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। फिलहाल तो जांच कमिटी की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाना चाहिए।

हत्या' शब्द विचित्रता और अज्ञान के नमूने

शंकर शरण

आरएसएस प्रशिक्षित नेताओं में विचित्रता तरह-तरह रूपों में दिखती है। बल्कि अधिकांश रूप में विचित्रता ही दिखती है! उन के बयानों, घोषणाओं, और कदमों, गतिविधियों से इस की लंबी सूची बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, विगत एक निश्चित अवधि में उन की पहली ऐसी घोषणा और नवीनतम कदम को लें।

पहली थी गंभीर संवैधानिक पदों से घोषणा करना कि उन्हें 'कांग्रेस मुक्त भारत' बनाना है। यह घोषणा संविधान-विरोधी, तथा करोड़ों देशवासियों के प्रति अपमानजनक थी। संविधान में दूर-दूर कोई संकेत तक नहीं कि किसी संवैधानिक पदधारी को किसी वैध राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन को मिटा देने का प्रयत्न करना है। अतः वह घोषणा ही साफ संविधान-विरोधी थी।

दूसरे, वह करोड़ों कांग्रेस-समर्थक देशवासियों का अपमान भी था जब उन के समर्थित दल? को मिटाने की घोषणा संवैधानिक पदधारी कर रहे थे! संवैधानिक पदधारी पूरे देश की संपूर्ण जनता के लिए है। उसे केवल अपने दल को हवा बांधने का काम संविधान ने नहीं दिया है। तब उन पदधारियों ने कहा से समझ लिया कि उन्हें करोड़ों नागरिकों को पसंद के एक राजनीतिक दल को मिटा देने का लक्ष्य रखना है? ऐसी सार्वजनिक घोषणा, ऐसी विचित्र डफ कर्म वही कर सकता है, जिसे संविधान, नैतिकता और शिष्टाचार की समझ नहीं है। यह समझ भी नहीं कि ऐसी अनावश्यक, दंभी घोषणा भविष्य में उलटे अपने मुंह पर गोबर पड़ने की संभावना अपने हाथों से बनाता है—यदि वह दल मिटने के बजाए बढ़ जाए (जो अभी-अभी हुआ)। सामान्य नेता ऐसी घोषणाएँ नहीं करते। केवल संघ-प्रशिक्षित असामान्य वर्ग में ऐसे मूढमति पनपते हैं जो लज्जा की बात पर गर्व करते, और ताली पीटते हैं।

वस्तुतः वह घोषणा अपने समर्थक मतदाताओं के प्रति भी अजुबा थी। जिन्होंने भाजपा को चाहे अन्य जिन चीजों के लिए भी मत दिया हो, उस में किसी दल को मिटा देने की बात नहीं थी। न उस चुनाव से पहले भाजपा के बयानों या घोषणापत्र में कहीं यह बात दर्ज थी, कि वे देश को 'कांग्रेस मुक्त' करने का लक्ष्य रखते हैं। अतः निर्वाचित होकर संवैधानिक पद संभाल लेने के बाद एकाएक वैसी घोषणा भाजपा समर्थक मतदाताओं के लिए भी अप्रत्याशित थी।

अब उन की नवीनतम करनी को लीजिए। उसी कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए उन्होंने एक 'हत्या' दिवस ही देश पर थोपा है! यह मूढता की परीकाष्ठा है। सब से पहले तो मानव निर्मित कामकाजी नियमों की एक संहिता, जिसे वैधानिक रूप से रोज संशोधित किया, बल्कि आमूल बदला हटाया जा सकता है, उसे किसी जीवित मनुष्य सा मानकर 'रक्षा' और 'हत्या' जैसी शब्दावली उतेजक और बचकानी है। क्योंकि यदि संविधान की 'हत्या' नामकरण उचित माना जाए, तब तो संविधान का हर संशोधन भी 'अंग-भंग' जैसा अपराध बनता है! जो अपराध खुद संघ-भाजपा के नेता गत वर्षों में सात बार कर चुके हैं। यानी, उन की रक्षा/हत्या शब्दावली में कहें तो, उन्होंने कभी संविधान की कोई अंग/हत्या काट दी, कभी उस के केश नोच लिए, कभी आंख में लकड़ी डाली, तो कभी घुटना घायल कर दिया। आखिर, यदि संविधान को 'हत्या' हो सकती है, तो उस की चमड़ी उधेड़ी जा सकती है, उस के कान काटे जा सकते हैं, उसे लांगड़ा बनाया जा सकता है, आदि। अतः संविधान जैसी कागजी निर्जीव वस्तु के लिए 'हत्या' शब्द ही अनुचित है।

दूसरे, ऐसे नाम का औपचारिक अनुष्ठान सब पर थोपना बच्चों-किशोरों-युवाओं की नई पीढ़ी की संवेदनाओं पर आघात है, जिसे 'हत्या' जैसी उतेजक चीज मनाने, दुहराने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

विचार-पक्ष

अर्थव्यवस्था को तीव्र गति एवं महाशक्ति बनाने वाला बजट

ललित गर्ग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम सम्पूर्ण बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, उनकी ओर से प्रस्तुत यह बजट एक मौलिक सोच एवं दृष्टि से दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिये आगे की राह दिखाते वाला है। संभावना है कि इस बजट में समावेशी विकास, वधियों को वरीयता, नौकरीपेशा का थोड़ी राहत, बुनियादी ढांचे में निवेश, पर्यटन को बढ़ावा, आदिवासी उन्नयन, क्षमता विस्तार, हरित एवं कृषि विकास, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी, मोदी के नये भारत-सशक्त भारत-विकसित पर बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने सरकार की 9 प्राथमिकताओं—खेती में उत्पादकता और मजबूती बढ़ाना, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, मानव संसाधन का समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, मैनुफैक्चरिंग और सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्वोरिटी, इंफ्रस्ट्रक्चर, इन्वोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स का एलान किया है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार को भी गति देगा। बजट में जहाँ बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है वहीं महंगाई को नियंत्रित करने की मंशा साफदिखाई दी है। विकास, स्टार्टअप और रोजगार सृजन के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान दिलाने के संकल्प को बल देने में सहायक बनेगा। सातवीं बार बजट प्रस्तुत कर वित्तमंत्री सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था।

सशक्त एवं विकसित भारत निर्मित करने, उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावण योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल अनूठी है, प्रेरक है। अमृत काल का विजय तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो इस बजट से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इस बजट में मध्यम वर्ग



को लम्बे अन्तराल के बाद 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बढ़ी राहत दी है। नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़कर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में भी कुछ अहम बदलाव करने का एलान किया है। मौजूदा नियमों के तहत एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस लिमिट को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी अनुसंधान और प्रोटेक्टाइव विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की घोषणा की। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा। मोबाइल फोन और मोबाइल वीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर वीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत तक का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे पहुंचाना का लक्ष्य है। 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए छत्रावास बनाए जाएंगे। छात्रवासों और क्लब के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से यह बजट कारगर साबित होगा, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, रोजगार के नये अवसर सामने आयेंगे, उत्पाद एवं विकास को तीव्र गति मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद इस बजट प्रावधानों के माध्यम से देश को स्थिरता की तरफ ले जाते दिखाई पड़ रहे हैं। बजट हर वर्ष आता है। अनेक विचारधाराओं वाले वित्तमंत्रियों ने विगत में कई बजट प्रस्तुत किए। पर हर बजट लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर ही जाता रहा है। लेकिन इस बार बजट ने अर्थव्यवस्था में नयी परम्परा के साथ राहत की साँसें दी है तो नया भारत-सशक्त भारत-विकसित के निर्माण का संकल्प भी व्यक्त किया है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रेलों का विकास, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ किसानों, आदिवासियों, गांवों और गरीबों को ज्यादा तवज्जो दी गयी है। सच्चाई यही है कि जब तक जमीनी विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास की गति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। इस बार के बजट से हर किसी ने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थीं और उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। विशेषतः नौकरीपेशा लोगों ने राहत की सांस ली है।

संभवतः इस बजट को नया भारत निर्मित करने की दिशा में लोक-कल्याणकारी बजट कह सकते हैं। यह बजट वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की दिशाओं को भी उद्घाटित करता है। आम बजट न केवल आम आदमी के सपने को साकार करने, आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है बल्कि यह देश को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उज्या गया महत्वपूर्ण एवं दूरगामी सोच से जुड़ा कदम है। बजट के सभी प्रावधानों एवं प्रस्तावों में जहाँ 'हर हाथ को काम' का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत यह बजट निश्चित ही अमृत बजट है। जिसमें भारत के आगामी 25 वर्षों के समग्र एवं बहुमुखी विकास को ध्यान में रखा गया है। वीते कुछ सालों में नरेन्द्र मोदी ने इकोनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है।

आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। बजट में दूरिज्म पर विशेष बल दिया गया है। पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। सरकार ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देगी, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आशा के अनुरूप ही बजट का फेकस किसानों, आदिवासियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, रोजगार, युवाओं की अपेक्षाओं, विकास और ग्रामीण क्षेत्र एवं पर्यटन पर रखा है। अपने ढांचे में यह पूरे देश का बजट है, एक आदर्श बजट है। इसका ज्यादा जोर सामाजिक विकास पर है। अक्सर बजट में राजनीति, वोटनीति तथा अपनी व अपनी सरकार की छवि-वृद्धि करने के प्रयास ही अधिक दिखाई देते हैं लेकिन बावजूद यह बजट राजनीति प्रेरित नहीं, देश प्रेरित है। इस बजट में जो नयी दिशाएँ उद्घाटित हुई हैं और संतुलित विकास, भ्रष्टाचार उन्मूलन, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था का जो संकेत दिया गया है, सरकार को इन क्षेत्रों में अनुकूल नतीजे हासिल करने पर खासी मेहनत करनी होगी।

न्यायालयों में पहले ही अपने घुटने छिलवा चुका था लोकतंत्र विरोधी प्रतिबंध

लोकेन्द्र सिंह राजपूत

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाकर नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की है। अब कर्मचारी संघ की गतिविधियों में सामान्य नागरिकों की भी शामिल हो सकेगी। निःसंदेह, सरकार का यह निर्णय लोकतंत्र और संविधान की भावना को मजबूत करनेवाला है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह विविध सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों में शामिल हो सके। एक सामान्य नागरिक की भाँति यह अधिकार कर्मचारियों को भी प्राप्त है कि अपने कार्यालयीन समय के बाद सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा हो सकते हैं। परंतु, लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना को कमजोर करते हुए तत्कालीन सरकार ने 58 वर्ष पहले 1966 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारी के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई का विधान भी रखा गया था। यह एक प्रकार से राष्ट्रीय विचार के प्रति झुकाव रखनेवाले लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास ही था। इस तानाशाही एवं द्वेषपूर्ण निर्णय का उत्तर संघ ने तो कभी नहीं दिया लेकिन समाज ने अवश्य ही आंदोलन दिखाने का कार्य किया। संघ को दबाने एवं समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। इस आदेश के अतिरिक्त तीन बार पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया। संघ की छवि खराब करने के लिए बड़े-बड़े नेताओं की ओर से मिथ्या प्रचार भी किया गया। अपने समर्थक बुद्धिजीवियों से पुस्तकें भी लिखवायी गईं। लेकिन संघ विरोधियों के ये सब प्रयास विफल रहे। निस्वार्थ भाव से देश और समाज के लिए कार्य करनेवाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई रोक नहीं सका। अपनी 99 वर्ष की यात्रा में संघ ने लगातार प्रगति एवं विस्तार ही किया है। अपने विचार, आचरण एवं सेवाकार्यों से संघ ने समाज का विश्वास जीता, जिसके कारण समाज सदैव संघ के साथ खड़ा रहा।

कई ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें संघ गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारों ने सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की। लेकिन वे सभी मामले न्यायालय में टिक नहीं सके। संघ के स्वयंसेवक न्यायालय से जीतकर आए। उनकी छोटी-छोटी जीतों की श्रृंखला ने भी यह साबित किया कि संघ की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए लगाया गया तत्कालीन सरकार का आदेश संविधान एवं मौलिक अधिकारों की मूल भावना के विरुद्ध था। इस प्रतिबंध को 1966 के बाद से ही चुनौती मिलने लगी



थी। क्योंकि संघकार्य को बाधित करने और स्वयंसेवकों को प्रताड़ित करने की जिस मंशा से सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया था, उसे अंजाम देने का कार्य देशभर में शुरू किया गया। इन प्रतिबंधों को हथियार बनाकर सरकारों ने देश के विभिन्न राज्यों में संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं की नौकरी छीनना शुरू कर दिया। सरकार की मनमानी को स्वयंसेवकों ने न्यायालयों में चुनौती दी, जहाँ सरकारों को मुंह की खानी पड़ी। मैसूर उच्च न्यायालय ने वर्ष 1966 में रानाथचर अग्निहोत्री की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया आरएसएस एक गैर-राजनैतिक एवं सांस्कृतिक संगठन है जो कि गैर-हिंदुओं के प्रति किसी भी द्वेष अथवा घृणा की भावना से मुक्त है। इसी क्रम में न्यायालय ने आगे कहा कि संघ ने भारत में लोकतांत्रिक पद्धति को स्वीकार किया है। अतः राज्य सरकार द्वारा याची को सेवा से हटाने का निर्णय गलत है। इसके साथ ही न्यायालय ने उक्त कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का निर्णय सुनाया। इसी प्रकार, वर्ष 1967 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के कर्मचारी रामपाल को पद से हटाने संबंधी आदेश को रद्द करते हुए कहा कि संघ कोई राजनैतिक संगठन नहीं है, अतः इसकी गतिविधियों में भागीदारी करना कानूनी रूप से गलत नहीं है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा रामपाल को पद से इस आधार पर हटाया गया था कि वे आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेते हैं एवं राज्य की दृष्टि में आरएसएस एक राजनैतिक संगठन है। 'भारत प्रसाद त्रिपाठी बनाम मध्यप्रदेश सरकार तथा अन्य' प्रकरण में तो 1973 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यहाँ तक कह दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यक्रम में भाग लेने के आधार पर किसी कर्मचारी को सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। किसी अंतरस्थ हेतु जारी किया गया (इस आशय का) कोई आदेश वैध नहीं ठहराया जा सकता। यानी

न्यायालय ने संघ की गतिविधि में शामिल होने से रोकने के लिए लगाए गए किसी भी प्रतिबंध/आदेश को अवैध करार दिया। इसके अलावा 'मध्यप्रदेश राज्य बनाम राम शंकर रघुवंशी तथा अन्य (1983)', मामले में उच्च न्यायालय, 'श्रीमती थाडुमकर बनाम महाप्रबंधक टेलीकॉम्यूनिकेशन्स, केरल मंडल (1982)' मामले में अर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय और 'डीबी गोहल बनाम जिला न्यायाधीश, भावनगर तथा अन्य (1970)' मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने यही निर्णय दिए कि संघ से जुड़े होने या उसके कार्यक्रमों में शामिल होने के आधार पर किसी कर्मचारी पर न तो कार्रवाई की जा सकती है और न ही उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है। कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं, जिनमें संघ के कार्यकर्ताओं को इस प्रतिबंध के लागू होने से पहले ही निशाना बनाया गया। इन मामलों से स्पष्ट है कि तत्कालीन सरकारें शुरू से ही चाहती थीं कि संघ के कार्यक्रमों में शामिल होनेवाले लोगों के मन में भय उत्पन्न किया जाए। ताकि हिन्दुओं के संगठन के कार्य को रोका जा सके। परंतु, न्यायापालिका से लेकर आमजन की कसौटी पर राष्ट्रीय विचार को कमजोर करने के सभी प्रयास विफल रहे। 'कृष्ण लाल बनाम मध्यभारत राज्य (1955)' में इंदौर स्थित मध्यभारत उच्च न्यायालय, 'चितामणि नुरगांवकर बनाम पोस्ट मास्टर जनरल, कें.मं., नागपुर (1962)' में बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर न्यायापीठ, 'जयकिशन महरोत्रा बनाम महालेखाकार (1963)' में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 'केदारलाल अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य (1964)' मामले में जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय और 'मनोहर अंबोकर बनाम भारत संघ तथा अन्य (1965)' प्रकरण में दिल्ली स्थित पंजाब उच्च न्यायालय ने यही कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैरकानूनी संगठन नहीं है। सरकारी कर्मचारी को संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने के आधार पर दंडित नहीं

किया जा सकता। यदि कोई सरकारी कर्मचारी संघ का सदस्य है तब भी उसे इस आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता। स्मरण रखें कि वर्ष 1932 में अंग्रेजों ने भी सरकारी कर्मचारियों के संघ से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजी हुकूमत की ओर से जारी परिपत्र में आदेश दिया गया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बनने अथवा उसके कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति नहीं रहेगी। कहा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए जिस प्रकार का प्रतिबंध कांग्रेस सरकार ने लगाया, वह औपनिवेशिक काल की अंग्रेजों की नीति को ही आगे बढ़ाने का कार्य था। बाद के वर्षों में जब राज्यों में राष्ट्रीय विचार का पोषण करनेवाली सरकारें आईं तो उन्होंने लोकतंत्र एवं मौलिक अधिकार विरोधी उच्च प्रतिबंध को राज्यों में समाप्त कर दिया। संघ ने इस प्रतिबंध की कभी चिंता नहीं की क्योंकि न्यायालयों में इस तुलनाकी फरमान के घुटने इतने अधिक छिल गए थे कि यह स्वतः ही निष्पत्ती ही गया था। फिर भी, वर्ष 2000 में जब संघ के तत्कालीन सरसंघचालक प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह 'रज्जू भैया' से पूछा गया कि संघ इस प्रतिबंध को लेकर क्या सोचता है? तब उन्होंने कहा था कि संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने अथवा हटाने की कार्यवाही में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसके निर्णय का अधिकार सरकारों के पास है। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने इस दिशा में सबसे पहला कदम उठाया। बाद में उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश की सरकारों ने भी प्रतिबंध को हटा लिया। यह प्रतिबंध केवल केंद्र सरकार में रह गया था, उसे भी वर्तमान केंद्र सरकार ने संघ के हस्तक्षेप के बिना, स्वतः ही समाप्ति करने के बाद हटा लिया है। केंद्र सरकार के निर्णय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी संतुलित टिप्पणी की गई है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा— राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय-समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा की है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था।



सूक्ष्म जीवों से फैलता है लाइम डिजीज

लाइम डिजीज रोग बोरेलिया बर्गडोरेफेरी नामक जीवाणु के काटने के कारण होता है। जिसे हिरण किलनिया नाम से जानते हैं। हर किसी को किलनियों द्वारा काटा जाना याद नहीं रहता, क्योंकि हिरण किलनी बहुत छोटी होती है और उसके काटने का किसी को ध्यान नहीं रहता। अगर आप इसके शिकार हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं।

रखा है तो आपका चिकित्सक कीट का निरीक्षण कर सकता है और उसे प्रयोगशाला में प्रजातियों की पहचान करने के लिए भेज सकता है। कुछ प्रयोगशालाएं ये देखने के लिए कि इसमें लाइम बैक्टीरिया है या नहीं किलनी का विश्लेषण कर सकती हैं। आपके लक्षणों और परीक्षण के आधार पर आपका चिकित्सक लाइम रोग का निदान करेगा। लाइम रोग के पहले चार से छह हफ्तों में रक्त परीक्षण अवसर नकारात्मक होते हैं। लाइम परीक्षण के मूल परीक्षण को ईएलआईएसए (एंजाइम-लिंक्ड इम्यूनोसोर्ट ऐससे) कहते हैं। लाइम डिजीज में ईएलआईएसए परिणाम की वेस्टर्न ब्लॉट नामक परीक्षण से पुष्टि करना पड़ती है। लाइम रोग के निदान में मदद और लक्षणों के अन्य कारणों की जांच के लिए प्रभावित जोड़ का तरल पदार्थ का एक

नमूना लिया जा सकता है। लाइम रोग प्रतिरक्षी और सूजन के परीक्षण और अन्य रोगों की जांच के लिए, मरिस्टिफ्कमैरु द्रव भी स्पाइनल टेप के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के चारों ओर से लिया जाता है।

लाइम डिजीज से बचाव

यदि आप ऐसे क्षेत्र में हैं, जहां लाइम रोग अधिक आम है, तो आप निम्न सावधानी बरत सकते हैं :-

- ▶ जंगल, बड़े झाड़ीदार मैदान और घास से बचें, जहां किलनिया छुपती हैं।
- ▶ लंबी पतलून और लंबी आस्तीन पहनें; सफेद कपड़े किलनियों को दूढ़ना आसान बनाते हैं। सफेद कपड़ों को कम यूज करें।

आरंभिक लाइम इन्फेक्शन के लिए चिकित्सक आमतौर पर तीन हफ्तों की एंटीबायोटिक दवाएं निर्धारित करते हैं। इसमें टेट्रासायक्लिन पेनीसिलिन एमोक्सिसिलिन, सेफ़ुरोक्सिम (सेफ्टिन) शामिल है। हृदय या तंत्रिका संबंधी समस्याओं से पीड़ित कुछ लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इलाज किया जाता है। जैसे सेफ़ोट्रियाक्सोन (रोसेफिन) दो से चार सप्ताह के लिए नसों में दिया जाएगा। अंतः शिरा उपचार की भी सलाह दी जा सकती है। डॉक्सीसायक्लीन को 8 साल से कम उम्र के बच्चों और जो महिलाएं गर्भवती हैं या परिचर्या कर रही हैं, को देने से बचना चाहिए। एरिथ्रोमायसिन, एजिथ्रोमायसिन या वलेरिथ्रोमायसिन कम प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन अवसर उन लाइम रोग से पीड़ित लोगों के लिए निर्धारित की जाती हैं, जो ऊपर दिए गए विकल्प बर्दाश्त नहीं कर सकते।

टीका उपलब्ध नहीं

लाइम रोग का टीका अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 2002 में कम बिक्री के कारण इसे बाजार से वापस ले लिया गया था और दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

- ▶ जंगली क्षेत्रों या लंबी घास के क्षेत्रों या झाड़ीदार मैदानों से लौटने के शीघ्र बाद अपनी त्वचा को किलनियों के लिए जांचें।
- ▶ किलनी निरोधक त्वचा और कपड़ों पर लगाएं। एंटीबायोटिक दवाएं हर किलनी के काटने पर निर्धारित नहीं की जाती, क्योंकि लाइम रोग होने का खतरा काफी कम होता है, अधिकांश क्षेत्रों में 0.1 प्रतिशत से कम से लेकर पूर्वोत्तर और मिडवेस्ट के कुछ क्षेत्रों में 5 फीसदी तक होता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि जिन क्षेत्रों में लाइम रोग की दर अधिक है, उन लोगों के लिए डॉक्सीसायक्लीन (डॉक्सी कैप्स और अन्य ब्रांड के नाम) की एक खुराक रोग से बचाव कर सकती है। लाइम डिजीज की बीमारी होने पर शीघ्र परामर्श लें।



लाइम डिजीज की चिकित्सा

शरमाना कहीं रोग न बन जाए

हर कोई शरमाता है। यहां तक कि बेशर्म कहे जाने वाले लोग भी शरमाते हैं। रोचक बात है कि शरमाना मानव का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। शर्म या लज्जा को स्त्री का जैवर कहा गया है। शरमाते पुरुष भी हैं। निश्चित ही यह मानव भावनाओं में एक है, जो चेहरे पर प्रकट होती है सो हर कोई शरमाता है, मगर जरूरत से ज्यादा शरमाना भाव की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि एक गंभीर रोग है।



एक लम्बे समय तक इसे सहज शारीरिक क्रिया माना गया तो कई महत्वपूर्ण और रोचक गुणधर्म खुली। शर्म से जुड़े तथ्यों ने ही इसे रोग की श्रेणी में ला खड़ा किया और नाम दिया गया एरोथ्रोफोबिया। स्नायुतंत्र से संबंधित शर्म मरिस्टिफ्क के निचले भाग हाइपोथैलमस द्वारा प्रभावित होती है। जब कोई शरमाता है तो हाइपोथैलमस हरकत में आ जाता है। यही निर्देश रक्त वाहिकाओं तक जा पहुंचता है, परिणामस्वरूप रक्त वाहिकाएं फैलने या सिकुड़ने लगती हैं। यह स्थिति चेहरे पर भाव परिवर्तन लाती है। इससे आंखों की पलकें विशेष अंदाज में उठने-गिरने लगती हैं। इसके अलावा गालों के उभार पर एक थिरकन पैदा हो जाती है। इसी कारण चेहरे पर लालिमा आ जाती है। अंग्रेजी में इसे ब्लश करना कहा जाता है। सामान्य तौर पर यह सब क्षणिक होता है, मगर रोग की स्थिति में यह देर तक हर कोई शरमाता है। यहां तक कि बेशर्म कहे जाने वाले लोग भी शरमाते हैं। रोचक बात है कि शरमाना मानव जाति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। शर्म या लज्जा को स्त्री का जैवर कहा गया है। शरमाते पुरुष भी हैं। निश्चित ही यह मानव भावनाओं में एक है, जो चेहरे पर प्रकट होती है सो हर कोई शरमाता है, मगर जरूरत से ज्यादा शरमाना भाव की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि एक गंभीर रोग है।

एरोथ्रोफोबिया कैसे होता है

एक लम्बे समय तक इसे सहज शारीरिक क्रिया माना गया तो कई महत्वपूर्ण और रोचक गुणधर्म खुली। शर्म से जुड़े तथ्यों ने ही इसे रोग की श्रेणी में ला खड़ा किया और नाम दिया गया एरोथ्रोफोबिया। स्नायुतंत्र से संबंधित शर्म मरिस्टिफ्क के निचले भाग हाइपोथैलमस द्वारा प्रभावित होती है। जब कोई शरमाता है तो हाइपोथैलमस हरकत में आ जाता है। यही निर्देश रक्त वाहिकाओं तक जा पहुंचता है, परिणामस्वरूप रक्त वाहिकाएं फैलने या सिकुड़ने लगती हैं। यह स्थिति चेहरे पर भाव परिवर्तन लाती है। इससे आंखों की पलकें विशेष अंदाज में उठने-गिरने लगती हैं। इसके अलावा गालों के उभार पर एक थिरकन पैदा हो जाती है। इसी कारण चेहरे पर लालिमा आ जाती है। अंग्रेजी में इसे ब्लश करना कहा जाता है। सामान्य तौर पर यह सब क्षणिक होता है, मगर रोग की स्थिति में यह देर तक रहता है और बार-बार होता है। रोगी इसमें आंतरिक आनंद की अनुभूति करता है सो बार-बार शरमाना चाहता है और रोग बढ़ता जाता है। शर्म के लक्षण शरीर में चेहरे पर ही नहीं, कई अन्य रूपों में भी देखे जा सकते हैं।

बीमारी के लक्षण

मसलन, शर्म की स्थिति में लड़कियां आंखें झुकाए पेर के आंगूठे से धरती या फिर फर्श को कुरेदने लगती हैं, बेवजह आंखें संवरने लगती हैं, उंगली पर दुपट्टा लपेटने लगती हैं। होंठों पर अंगुली रखना या फिर मुंह से अंगुली दबा लेना भी शर्म के लक्षण हैं। यही नहीं, शर्मसार होती लड़कियां अपना चेहरा भी छिपा लेती हैं। इस कृच्य से वह अपनी शर्म छुपाती नजर आती हैं, मगर हकीकत में यह शर्म को और उभारना है। चेहरे पर आई शर्म छिपाने से नहीं छिपती है, बल्कि इस बात का स्पष्ट करती है कि शर्म का अतिरेक है, लाख छिपाने पर भी नहीं छिपेगा।

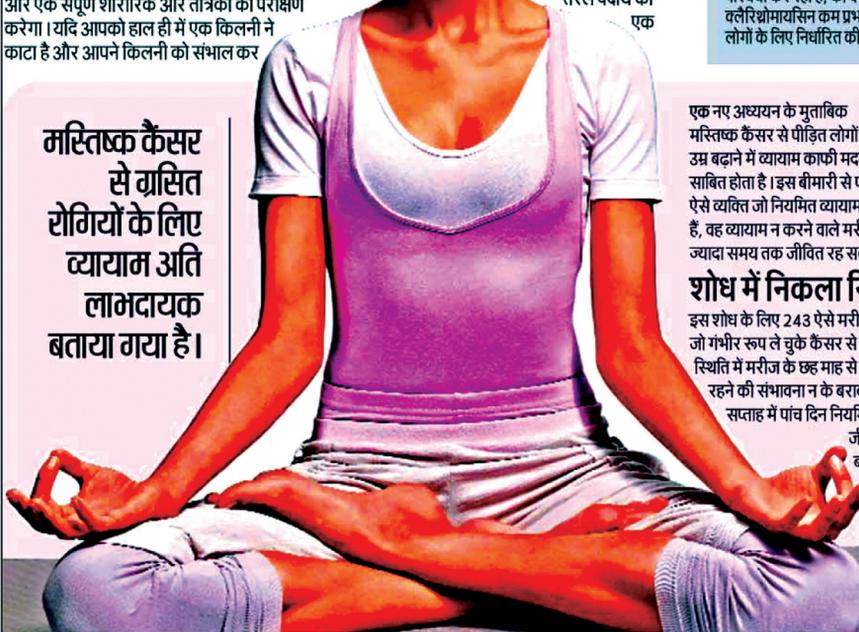
गठिया पीड़ित में बीमारी अधिक

लगभग 10 फीसदी लाइम गठिया पीड़ित लोगों को एंटीबायोटिक दवाएं लेने के बावजूद स्थाई जोड़ों की सूजन होने लगती है। हाल ही के प्रमाण सुझाते हैं कि यह स्वप्रतिरक्षित प्रभाव के कारण होता है, जिसमें लाइम संक्रमण प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के अपने कोशिकाओं पर हमला करने के लिए सक्रिय करते हैं। ये समस्या कुछ आनुवांशिक प्रकार के लोगों में पाई जाती है। ऐसे लोग जारी रखी गई एंटीबायोटिक दवाओं की बजाय ऐसी दवाओं को प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देती हैं।

लाइम डिजीज का निदान

आपका चिकित्सक आपके लक्षणों के बारे में पूछेगा और एक संपूर्ण शारीरिक और तंत्रिका का परीक्षण करेगा। यदि आपको हाल ही में एक किलनी ने काटा है और आपने किलनी को संभाल कर

मरिस्टिफ्क कैंसर से ग्रसित रोगियों के लिए व्यायाम अति लाभदायक बताया गया है।



एक नए अध्ययन के मुताबिक मरिस्टिफ्क कैंसर से पीड़ित लोगों की उम्र बढ़ाने में व्यायाम काफी मददगार साबित होता है। इस बीमारी से पीड़ित ऐसे व्यक्ति जो नियमित व्यायाम करते हैं, वह व्यायाम न करने वाले मरीजों से ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं।

शोध में निकला निष्कर्ष

इस शोध के लिए 243 ऐसे मरीजों का चुनाव किया गया, जो गंभीर रूप से मरिस्टिफ्क कैंसर से पीड़ित थे। आमतौर पर इस स्थिति में मरीज के छह माह से अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना न के बराबर होती है। ऐसे मरीज जो सप्ताह में पांच दिन नियमित व्यायाम करते थे, उनका जीवनकाल महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गया। वे औसत 21.84 माह तक जीवित रहे,

बढ़ जाती है जिंदगी

नार्थ कैरोलिना के ड्यूक कैंसर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन में कहा गया है कि व्यायाम कैंसर से पीड़ित मरीज पर इलाज और इलाज के बाद की स्थिति में सकारात्मक असर डालता है और इससे उनकी जिंदगी बढ़ सकती है।

व्यायाम से दूर करें मरिस्टिफ्क कैंसर

जबकि व्यायाम नहीं करने वाले मरीज केवल 13.03 माह ही जीवित रह सके।

परखने की जरूरत

शोध से जो शुरुआती तथ्य सामने आए हैं, उसे और गहनता से परखने की जरूरत है। व्यायाम का लक्षणों पर असर जानने के अलावा बीमारी के विकास और अस्तित्व पर भी इसके प्रभाव को समझना होगा। यह शोध जर्नल ऑफ वलीनिकल ऑन्कोलॉजी के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित हुआ है।

एनीमिया के लिए रामबाण चुकंदर

चुकंदर की पत्तियों में विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कन्द व इसकी पत्तियां रक्त निर्माण के अलावा हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं। चुकंदर में पोटेसियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज व रेशे की पर्याप्त मात्रा होती है। पाचन योग्य शर्करा की उपस्थिति के कारण चुकंदर का सेवन ऊर्जा भी प्रदान करता है।

निरोग रखता है
ऐसा समझा जाता है कि चुकंदर का गहरा लाल रंग इसमें लौह तत्व की प्रचुरता के कारण है, लेकिन सच यह है कि चुकंदर का गहरा लाल रंग इसमें पाए जाने वाले एक रंगकण (बीटा सायानिन) के कारण होता है। एण्टी ऑक्सिडेंट गुणों के कारण ये रंगकण स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। चुकंदर में पाए जाने वाले फोलिक एसिड, पोटेसियम व मुलायम रेशा भी इसके पोषणिक गुणों को बढ़ाते हैं। चुकंदर का नियमित सेवन सम्पूर्ण

शरीर को निरोग रखने में सहायक है। नियमित खाने से अन्य रोगों में लाभ होता है।

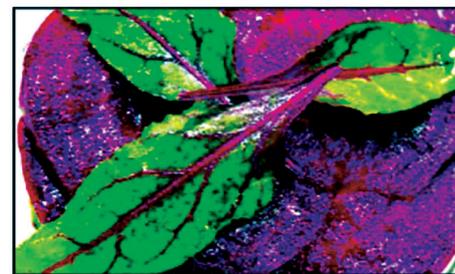
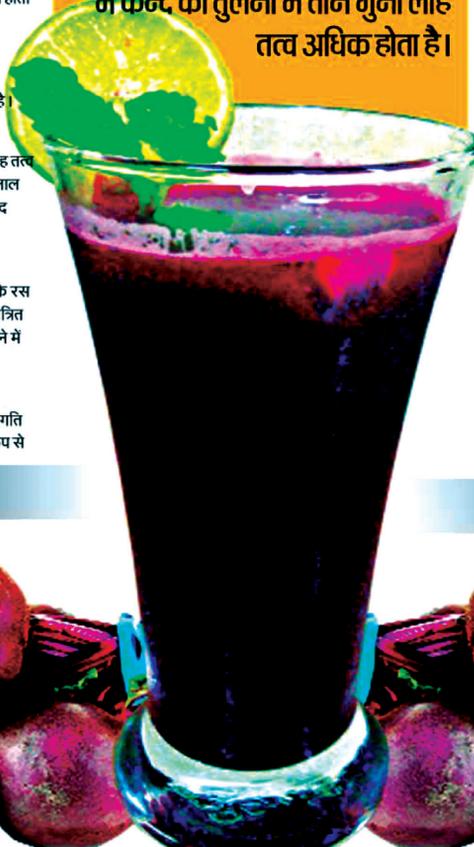
एसीडोसिस
चुकंदर की क्षारीयता शरीर में एसीडोसिस को रोकने में सहायक है।

रक्त-अल्पता
चुकंदर से प्राप्त उच्च गुणवत्ता का लौह तत्व रक्त में हीमोग्लोबीन का निर्माण व लाल रक्तकणों की सक्रियता के लिए बेहद प्रभावशाली है।

रक्तचाप
विशेषज्ञों का मानना है कि चुकंदर के रस का नियमित सेवन रक्तचाप को नियंत्रित रखता है। उच्च रक्तचाप में कमी लाने में भी चुकंदर गुणकारी है।

कब्ज
चुकंदर का मुलायम रेशा आंतों की गति बनाए रखता है। इसको नियमित रूप से

खून की कमी यानी एनीमिया की शिकार महिलाओं के लिए चुकंदर रामबाण के समान है। चुकंदर के कन्द के अलावा चुकंदर की हरी पत्तियों का सेवन भी बेहद लाभदायी है। इन पत्तियों में कन्द की तुलना में तीन गुना लौह तत्व अधिक होता है।



खाने से लम्बे समय से चली आ रही कब्ज से भी मुक्ति मिल जाती है।

रक्त संचार ठीक

चुकंदर के रस का नियमित सेवन रक्त नलिकाओं में कैल्शियम के जमाव को हटाकर उनका लचीलापन बनाए रखता है, जिससे रक्त संचरण सुगमता से होता है।

कैंसर से बचाव

चुकंदर में पाए जाने वाले अमीनो एसिड में कैंसररोधी तत्व पाए जाते हैं। शोध अध्ययनों से पता चला है कि चुकंदर के रस के नियमित सेवन से कैंसरकारक तत्वों का निर्माण बाधित होकर पाचन तंत्र की कार्यक्षमता को बढ़ावा मिलता है।

विषैले तत्व नष्ट

चुकंदर के रस का नियमित सेवन न केवल यकृत, बल्कि सम्पूर्ण पाचन तंत्र

के हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालकर आरोग्य प्रदान करता है। चुकंदर के साथ यदि गाजर मिलाकर इसके रस का सेवन किया जाए तो यह पिताशय व वृक्क से हानिकारक तत्वों को हटाकर इन अंगों की कार्यक्षमता बढ़ाता है।

चुकंदर की पहचान

खाने के लिए पत्तीदार चुकंदर का चयन करें। पत्ती सहित चुकंदर को 3-4 दिन रेफ्रीजरेटर में संग्रह करने पर इनकी पत्तियों की नमी बनी रहती है, जबकि पत्तियों के बिना चुकंदर को लगभग दो सप्ताह तक संग्रह किया जा सकता है। जिन चुकंदर का तल गोलाई लिए होता है, वे अपेक्षाकृत अधिक स्वादिष्ट होता है। ताजे व कच्चे चुकंदर में एक विशेष खुशबू होती है, जो इसके स्वाद को बढ़ाती है।

सावधानियां

चुकंदर का सेवन उन व्यक्तियों को न्यूनतम ही करना चाहिए, जिन्हें गुर्दे में पथरी की समस्या है। चुकंदर का सेवन शक्तिवर्धक होने के साथ-साथ शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालता है, अतः इसके सेवन की शुरुआत थोड़ी मात्रा से करें। पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक इस प्राकृतिक विलंजर को अपने आहार में रस, सलाद व अन्य व्यंजनों के रूप में शामिल कर स्वस्थ व निरोग रहें।

सलाद के साथ चुकंदर

भारतीय भोजन थाली में सलाद के रूप में चुकंदर का उपयोग काफी प्रचलित है। गहरे लाल बैंगनी रंग का यह कन्द प्रायः शरीर में खून बढ़ाने के गुण के कारण खाया जाता है। लौह तत्व के अलावा चुकंदर में विटामिन भी भरपूर पाए जाते हैं। इसके नियमित सेवन से विटामिन ए, बी, बी 1, बी 2, बी 6 व विटामिन सी की पूर्ति सहज ही हो जाती है। शायद कम लोग ही जानते हैं कि चुकंदर में लौह तत्व की मात्रा अधिक नहीं होती है, किन्तु इससे प्राप्त होने वाला लौह तत्व उच्च गुणवत्ता का होता है, जो रक्त निर्माण के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि चुकंदर को सेवन शरीर से अनेक हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में बेहद लाभदायी है।



संक्षिप्त समाचार

सीमारानी प्रधान को मिली पीएचडी को उपाधि



शंकर लहरे/सरायपाली (समय दर्शन)। शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुन्द में हिंदी विभाग में पदस्थ सहायक प्राध्यापक एवं ग्राम हरदी निवासी सीमारानी प्रधान

पति युगल किशोर प्रधान को 'बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के छत्तीसगढ़ी काव्य में राष्ट्रीय चेतना' विषय पर पीएचडी की उपाधि मिली है। इन्होंने अपना शोध कार्य शोध निर्देशक, डॉ अनुसुइया अग्रवाल, डी. लिट् प्राचार्य, शास महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुन्द एवं सहायक शोध निर्देशक डॉ शीला दानी सहायक प्राध्यापक शास. कला एवम् वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर, रायपुर के निर्देशन में पूरा किया। इनका शोध केंद्र, शा.कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर रायपुर रहा है। साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध सीमारानी का जन्म फूलझर अंचल के ग्राम मोहका में पिता प्रेमलाल साहू एवं माता श्रीमती मालती साहू के घर हुआ था। बचपन से ही मेधावी रही श्रीमती प्रधान की प्रारंभिक शिक्षा गांव की स्कूल में हुई। कुछ समय मिडिल स्कूल भूकेल में शिक्षिका के पद पर भी पदस्थ रही। उन्होंने बताया कि घर गृहस्थी का काम के साथ-साथ पीएचडी की डिग्री हासिल करना एक बड़ी चुनौती भरा काम था। एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं। श्रीमती प्रधान लेखन कला के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इनके द्वारा लिखा शिव भजन रिलीज हो चुका है जिसको फिल्मी गायक सुरेश वाडेकर ने अपना स्वर दिया है। इनका साझा कविता संग्रह कुसुम, छत्तीस रागिनियां, नई मंजिलें, प्रथमा, भारत रत्न प्राप्त विभूतियों पर, अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों, भारतीय संस्कृति पर आधारित साझा संग्रह, शहीद वीर नारायण सिंह, थर्ड जेंडर आधारित लघु कथा का प्रकाशन हो चुका है। इसके अतिरिक्त नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर व्याख्यान विविध विषयों पर शोध परक व विमर्श आधारित साझा संग्रह प्रकाशित हो चुका है। हिंदी, ओड़िया, छत्तीसगढ़ी, संबलपुरी, लरिया में लेखन कार्य एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए वर्तमान में बाबा विशासहे कुल कोलता समाज के आंचलिक सभा रायपुर के उपाध्यक्ष हैं।

हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी द्वितीय मुख्य परीक्षा शुरु, उड़नदस्ता दल द्वारा परीक्षा केंद्रों का किया गया निरीक्षण

बलौदाबाजार/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा संचालित हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी द्वितीय मुख्य एवं अवसर परीक्षा 2024 जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही है। हायर सेकेण्डरी परीक्षा 23 जुलाई से तथा हाई स्कूल परीक्षा 24 जुलाई से प्रारम्भ हो गया है। परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग पर अंकुश लगाने, निरीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं परीक्षा के सफल आयोजन हेतु उद्देश्य, अनुभाग एवं विकासखण्ड स्तरीय 7 उड़नदस्ता दल गठित किया गया है। उड़नदस्ता दल प्रभारी डिप्टी कलेक्टर श्री अरुण कुमार सोनकर ने बुधवार को परीक्षा केंद्र स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शासकीय पंडित चक्रपाणी शुक्ल हायर सेकेण्डरी स्कूल बलौदाबाजार एवं पण्डित लक्ष्मी प्रसाद तिवारी शासकीय कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल बलौदाबाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संचालित परीक्षा संचालित होते पाया गया। बताया गया कि हायर सेकेण्डरी द्वितीय मुख्य एवं अवसर परीक्षा 23 जुलाई से 12 अगस्त तक प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 12:15 बजे तक तथा हाई स्कूल परीक्षा 24 जुलाई से 8 अगस्त तक प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 12:15 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी।

मेटा एआई अब हिंदी और अन्य भाषाओं में उपलब्ध है; अब अधिक रचनात्मक और स्मार्ट है

हम अपने ऐप्स और डिवाइस में Meta AI असिस्टेंट को पहुँच बढ़ा रहे हैं और नई सुविधाएं जोड़ रहे हैं ताकि आपको उत्तर देने, विचार करने और प्रेरणा मिल सके। Meta AI अब 22 देशों में उपलब्ध है, जिसमें अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरू और कैमरून शामिल हैं। अब आप WhatsApp, Instagram, Messenger और Facebook पर Meta AI के साथ नई भाषाओं में भी बात कर सकते हैं। यह सुविधा अब हिंदी, रोमन हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, पुर्तगाली, और स्पेनिश में उपलब्ध है और जल्द ही और भी भाषाएँ जोड़ी जाएंगी। WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook YōU meta.ai पर Meta AI को मदद से लोग कम समय में ज्यादा काम कर पा रहे हैं।

पलसापाली उपभोक्ता केन्द्र में चावल की हेराफेरी, सेल्समैन के द्वारा लगभग 45 क्विंटल चावल बेचे जाने का मामला

बसना (समय दर्शन)। जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा बसना अंतर्गत साख सहकारी समिति अंकोरी के उपभोक्ता केन्द्र पलसापाली में गरीबों को वितरण किये जाने वाले पी डी एस चावल को सेल्समैन द्वारा एकमुस्त लगभग 45 क्विंटल चावल बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया है।

बता दें कि केन्द्रीय शाख सहकारी समिति बैंक शाखा बसना के अंतर्गत सरकारी समिति अंकोरी उपभोक्ता केन्द्र के सेल्समैन बसंत दीप के द्वारा लगभग 45 क्विंटल चावल बेचे दिया गया है। पी डी एस का चावल नहीं मिलने से पलसापाली के ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि जुलाई माह का



चावल नहीं मिला है वहीं सरपंच चतुर्भुज राशनकार्ड धारकों को चावल मिला है। प्रधान ने बताया कि गांव के लगभग 54 बाकी लोगों को नहीं मिल पाया है।

पंचनामा बनाकर इसकी शिकायत की गई है। सुपरवाइजर भी जांच में आये थे। समिति प्रबंधक छेदू निपाद ने कहा कि सोसायटी में राशन का मिलान किया गया जिसमें 45 क्विंटल चावल और 03 क्विंटल शक्कर कम पाया गया है। बसंत दीप को नोटिस दिया गया है। सूत्रों से पता चला है कि सेल्समैन बसंत दीप द्वारा इस घटना से पहले भी कायतपाली, एवं अन्य उपभोक्ता केन्द्र भी गरीबों के हक की चावल को बेच खया था, विभागीय मिली भगत से हमेशा ऐसे भ्रष्टाचार को दबा दिया जाता है। केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा गरीबों को सशक बनाने में राशन वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त में चावल दिया जा रहा है जिसे सहकारिता विभाग के ही कर्मचारियों

के द्वारा गरीबों के पेट में लात मारकर बेचा जा रहा है। क्या ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होना चाहिये? अब देखना यह है कि गरीबों की राशन को बेचने वाले सेल्समैन के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है या नहीं यह अंधेरे में है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पलसापाली उपभोक्ता केन्द्र में फिलहाल चावल की व्यवस्था की जा रही है विभाग को माने तो विक्रेता बसंत दीप के द्वारा गबन किया गया चावल को वसूली किया जायेगा।
**दिव्यांशु देवांगन
खाद्य निरीक्षक,
बसना**

फसल बीमा राशि नहीं मिलने से किसानों में रोष

शंकर लहरे/महासमंद। एक तरफ शासन प्रशासन द्वारा फसल बीमा कराए जाने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाई जा रही है वहीं दूसरी ओर पिछले रबी सीजन में कराये गए फसल बीमा का लाभ किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है। पिछले रबी सीजन में हुई ओलावृष्टि से बिछियां सागरपाली रोहिना क्षेत्र के बिछियां सागरपाली रोहिना क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ रबी फसल को काफी नुकसान पहुंचा था। खासकर गेहूं फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि का प्रकोप सागरपाली रोहिना के आसपास के गांव में ज्यादा था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा फसल क्षति का आकलन भी करवाया गया तथा हल्का पटवारी द्वारा आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा प्रकरण तैयार कर तहसील कार्यालय में 16.04.2024 को जमा किया गया है। रोहिना एवं बिछियां के किसानों ने गेहूं फसल के लिए बीमा भी करवाया था जिसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है।

पिछले 20 मार्च को सागरपाली रोहिना क्षेत्र में भयंकर ओलावृष्टि हुई जिसके चलते रबी फसल बर्बाद हो गई जिन किसानों ने गेहूं, मूंग, उड़द आदि फसल लिए थे बर्बाद भी फसल को देखकर माथा पकड़ लिये।

ओलावृष्टि से रोहिना, कापुडीह, दुर्गापाली, सागरपाली, बिजराभांठा, बिरसिंगपाली बुधुडोंगर आदि गांव में व्यापक रूप से क्षति हुई है। किसानों ने बताया कि पहली बार इतने बड़े-बड़े ओले गिरते हुए देखा था। आधे घंटे की ओलावृष्टि से लहलहाती फसल चौपट हो गई। रोहिना के रूपानंद साहू ने बताया कि गेहूं पककर कटाई के लिये तैयार थी ऐसे समय में ओलावृष्टि होने से पूरी तरह से गेहूं झड़ कर नीचे गिर गया और उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। उसने करीब 5 एकड़ में गेहूं की फसल ली थी जहां पिछले वर्ष करीब 80

पैकेट हो गया था इस बार मुश्किल से 25 पैकेट हुआ है। वीरेंद्र सेठ ने बताया कि गेहूं बोया था ओला गिरने से पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लागत भी नहीं निकल। सागरपाली के वृंदावन साहू ने बताया कि उसने गेहूं और मूंग लगाया था ओलावृष्टि को वजह से पूरी तरह से चौपट हो गया। किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ बीमा कराया था। बीमा के लिये किसान कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनी का चक्कर काटने विवश हैं। किसानों ने तत्काल फसल बीमा राशि दिलाए जाने की मांग शासन से की है।

कलर्स 'खतरों के खिलाड़ी 14' के साथ आपकी स्क्रीन पर चीखों से भरपूर छुट्टी लेकर आया है

रायपुर। किस्मत साहसी का साथ देती है, लेकिन रोमानिया में, नसीब निडर का साथ देगा! 'टूरिस्ट ट्रेप' की अपनी धारणा को फिर से रचने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कलर्स पहली बार रोमानिया में फेब्रिआ फेस्ट्स की अपनी टुकड़ी को ले जाकर छुट्टियों की स्क्रिप्ट को पुनः लिखते हुए, भारत के पसंदीदा स्टंट-आधारित शो *S39, खतरों के खिलाड़ी*S39; का 14वां सीजन पेश कर रहा है। 'रोमानिया में डर की नई कहानियां' थीम के साथ, इस शो के प्रतियोगी चाहे जितनी भी साहसी तैयारियां कर लें लेकिन यह डरावनी छुट्टी निश्चित रूप से उन्हें हिलाकर रख देगी। इस संस्करण की सभी नवीनताओं के बीच, शो का एक पहलू नियत बना हुआ है, वह है ब्लॉकबस्टर फिल्ममेकर और अवॉर्ड विजेता टीवी होस्ट, रोहित शेट्टी का मेजबान के रूप में अपनी भूमिका को दोहराना और अपने व्यापक अनुभव से डेयरडेविल्स को सलाह देना।

बच्चों, गर्भवती और शिशुवती माताओं के हिस्से की पोषक तत्व उनको मिलना चाहिए, सिर्फ रजिस्टर में एन्ट्री नहीं होनी चाहिए: कलेक्टर धर्मेश साहू



कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक ली

सारंगढ़ बिलाईगढ़ (समय दर्शन), कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा समय सीमा की बैठक में की। बैठक में कलेक्टर ने शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों से शासन द्वारा दिए गए राशन की राशि खाद्य विभाग में जमा करने के लिए निर्देशित किया।

कलेक्टर ने राजीव युवा मितान क्लब अंतर्गत अब तक शेष बचे राशि को वितरण नहीं करने के निर्देश सभी सीईओ को दिए। कलेक्टर ने प्रभारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी को कहा कि जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों, गर्भवती और शिशुवती माताओं के हिस्से की पोषक तत्व उनको मिलना चाहिए, सिर्फ रजिस्टर में एन्ट्री नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने आधार अपडेट, आयुष्मकार्ड निर्माण, पीएम विश्वकर्मा

योजना, कृषि विभाग अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि में आधार सीडिंग और भूमि सीडिंग, खाद बीज वितरण, खाद की मांग, भंडारण और वितरण के संबंध में तैयारी और व्यवस्था, जल संसाधन विभाग द्वारा भू-अर्जन, बरमकेला क्षेत्र में सड़क मरम्मत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बरसात के दिनों में पेयजल से होने वाले रोगों के रोकथाम के लिए क्लोरीन की दवा का छिड़काव, पेंशन योजनाओं के सत्यापन के बाद रिपोर्ट, स्कूल जलन योजना अंतर्गत निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा जांच के बाद रिपोर्ट, सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों की रिपोर्ट, आंगनबाड़ी केन्द्रों में जर्जर भवनों के मरम्मत के लिए सूची और मरम्मत की लागत की सूची आदि के बारे में अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस अवसर पर जिले के अधिकारीगण उपस्थित थे।

श्री वाटिका वृद्धाश्रम में विशेष शिविर का किया गया आयोजन, 60 से अधिक बुजुर्गों का किया नेत्र जांच

बलौदाबाजार (समय दर्शन)।

कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत विभिन्न विभागों से समन्वय करते हुए समाज कल्याण विभाग बलौदाबाजार द्वारा संचालित श्री वाटिका वृद्धाश्रम में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, आधार सेवा केन्द्र, जनपद पंचायत बलौदाबाजार एवं समाज कल्याण के कर्मचारी उपस्थित रहे। जिसमें कुल 121 वृद्धजन एवं दिव्यांगजन उपस्थित हुए। नेत्र संबंधी 64 वृद्धजनों का जांच किया गया, जिसमें 05 नेत्र ऑपरेशन, 17 चश्मा, आंखों में खुजली, आंखों में पानी आना, आंखों में जाला नेत्र संबंधी



समस्याएं एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए दवाईया भी प्रदाय की गई, तथा 12 वृद्धजनों का आधार कार्ड, एवं 05 वृद्धजनों को छड़ी वितरण किया गया। इस अवसर पर उप

संचालक समाज कल्याण अधिकारी, जनपद पंचायत के समाज शिक्षा संगठक, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आधार सेवा केन्द्र, के कर्मचारी एवं सचिवगण उपस्थित रहे।

पूर्व महासचिव नरोत्तम कटकवर पर लाखों रुपए गबन करने का आरोप

समाज के पदाधिकारियों ने एसपी, कलेक्टर, डीईओ व थाना प्रभारी को लिखित ज्ञापन सौंपकर की कार्यवाही की मांग

जांजगीर। कहरा समाज के महासचिव द्वारा समाज के लाखों रुपयों को गबन करने का आरोप कहरा समाज के अन्य पदाधिकारियों ने लगाते हुए कार्यवाही की मांग को लेकर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा, कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा, जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चाम्पा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जांजगीर-चाम्पा, शिवरीनारायण थाना प्रभारी को लिखित ज्ञापन सौंपे हैं। अपने ज्ञापन में समाज के अन्य पदाधिकारी ने बताया कि नरोत्तम कटकवर पिता बिसाहू कटकवर जो कि प्राथमिक शाला पुटपुरा में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत है, जिसके विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में विगत 5 फरवरी 2023 को धारा 294, 506, 323, 324, 325 एवं 34 के तहत अपराध दर्ज हैं। जो कि वर्तमान में न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ़ में

विचाराधीन है। समाज के लोगों ने बताया कि 12 जनवरी 2023 से 24 फरवरी 2024 तक नरोत्तम कटकवर कहरा समाज का महासचिव के पद पर था। उक्त कार्यकाल में समाज की राशि लगभग 51 लाख रुपये समाज के अन्य पदाधिकारियों सहित इनके द्वारा समाज के बैंक खाते में जमा न रखकर अपने पास नागद रखे हैं और उसका दुर्विनियोग किये है। अब नरोत्तम कटकवर का महासचिव का पद का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी उक्त रकम को समाज में जमा नहीं किये है एवं समाज के बार-बार बोलने पर भी राशि समाज को हस्तांतरित करने से मना कर रहे हैं। जो कि आर्थिक अनियमितता बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग (अमानत में खयानत) की श्रेणी का अपराध है जिसकी शिकायत की गयी है। समाज के लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी से अपराधिक व अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्यवाही की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा से उक्त व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गयी है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से समाज के अध्यक्ष मुकेश कुमार राकेश,

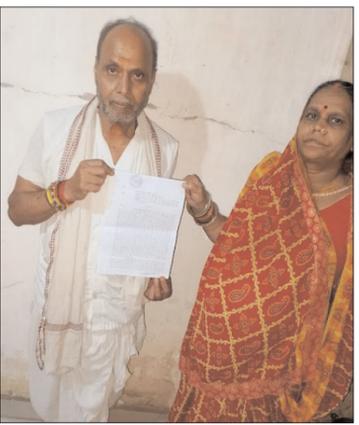
हरियर आदित्य, पुनिलाल कहरा, गुहाराम कहरा, राकेश कहरा, देवव्रत कहरा, रामशरण कहरा, जीवन कहरा, कुंदन आदित्य सहित बड़ी संख्या में कहरा समाज के लोग मौजूद थे।

मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ का आयोजन 25 को

भिलाई। दुर्ग स्थित मेहन्दा रिसोर्ट में पहली बार मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता का आयोजन 25 जुलाई की शाम 4 बजे से आयोजित होगा। इसमें सुभित्ता सेन, लारा दत्ता, उर्वशी रौतेला, हरनाज संधू जैसे कई हस्तियां देश का नाम रोशन कर चुकी है। मिस एशिया पेंसिफिक 2024 सोफिया सिंह जग होंगी। मिस इंडिया क्लासिक 2024 की स्टेट डायरेक्टर गीत सोन ने बताया कि डायरेक्टर निखिल आनंद के मार्गदर्शन में ग्लैमनाट के बैनर तले आयोजित मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता में प्रदेश से कई प्रतिभागी शामिल होंगी। फइनलिस्ट का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने और फिर वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाएगा।

आठ लोगों ने घर घुसकर मारपीट की पुलिस अधीक्षक से हुई शिकायत

सारंगढ़ (समय दर्शन)। जिला मुख्यालय के कोसीर थाना अंतर्गत ग्रांप उच्चमिड्डी का मामला है। प्रार्थीया लक्ष्मीन के पुत्र रमेश चन्द्रा पिता जयराम चन्द्रा निवासी ग्राम उच्चमिड्डी के द्वारा दर्ज करायी गयी एफआईआर नंबर 0150 में संलग्न चार अन्य अभियुक्त गण का नाम दर्ज करने वही ग्राम बोरसी थाना जैजपुर कलेश कुमार चन्द्रा, नरसिंह चन्द्रा, लालू चन्द्रा, देवीलाल चन्द्रा, विकास चन्द्रा, मयाराम अश्वनी चन्द्रा, द्वारिका चन्द्रा ग्राम कुटारबोर देवचंद चन्द्रा कुटारबोर सब एक मत होकर आपराधिक बदनियति से प्रार्थीया के गृहगाम उच्चमिड्डी आये और मेरे पति जयराम चन्द्रा तथा पुत्र रमेश चन्द्रा को धमकाते हुये यह कहने लगे कि - तुम हमारी बेटी लताबाई चन्द्रा के साथ हमेशा झगड़ा झंझट क्यों करते हो ? कहते हुये आवेश में आकर एकदम से गाली-गल्लो करतें हुये हाथ



मुक्का लात घुसों से मारपीट किये। घटना स्थल में ग्राम उच्चमिड्डी का सरपंच सोनूचंद यादव पिता फगू लाल यादव भी थे। जिन्होंने बीच बचाव करने की भरसक प्रयत्न किये, फिर भी वे लोग अति जोश व क्रोध में थे मेरी पुत्रवधु श्रीमती लताबाई चन्द्रा को मेरे पुत्र की अनुमति व हम दोनों सास ससुर के बिना पूछे जबरदस्ती अपने वाहन में ले जाने लगे तब सरपंच द्वारा मेरे पति जयराम चन्द्रा को यह कहा कि - गांव के कोटवार व गांव के एक दो अन्य व्यक्तियों को भी बुला लो। विदित हो कि - मेरे पति घर निकलने लगे तब उसी समय मेरे पति जयराम चन्द्रा पर कलेश कुमार चन्द्रा, नरसिंह चन्द्रा व लालू चन्द्रा हाथ मुक्का लात घुसों से मारपीट करने लगे। जिसे सरपंच द्वारा छुड़ाते हुये बीच-बचाव किया। आठों व्यक्ति मिल जुलकर घेरकर मेरे पुत्र रमेश चन्द्रा से भी मारपीट करते रहे।

इस तरह घर में उक्त घटना के समय भारी हंगामा किये। कलेश एव विकास चन्द्रा दोनों मुझे भी मुक्का से मेरे मुंह को मारा जिससे मेरे दांत ओठ फटकर खून बहने लगा। उपरोक्त घटना की रिपोर्ट मेरे पुत्र रमेशचन्द्रा के द्वारा पुलिस थाना कोसीर में मौखिक एवं लिखित में दिया है। किन्तु एफआईआर में सिर्फ ऊपर के चार लोग कलेश कुमार चन्द्रा, नरसिंह चन्द्रा, लालू चन्द्रा व मेरे पति जयराम चन्द्रा का ही नाम उल्लेखित है। जबकि उक्त एफआईआर में विकास चन्द्रा, अश्वनी चन्द्रा, द्वारिका चन्द्रा व देवचंद चन्द्रा का नाम गायब है। उक्त एफआईआर में आरोपी विकास चन्द्रा, अश्वनी चन्द्रा, द्वारिका चन्द्रा, देवलाल चन्द्रा का नाम जोड़ कर चालान प्रस्तुत करने व घर में अवैधानिक रूप से दल बल के साथ घर घुसकर मार पीट करने के आरोप भी धारा में दर्ज करने की शिकायत एसपी से की गई है।

खबर-खास

केंद्रीय बजट सराहनीय : अमित



गरियाबंद (समय दर्शन)। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट लोकसभा में पेश किया। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सातवां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। अमित खारिया ने बजट को सराहनीय और स्वागतयोग्य बताया। अमित खारिया ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के आधार पर जो बजट पेश किया गया है। उसके लिए बधाई देता हूँ। मोदी सरकार के इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बजट में युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया, वित्त मंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों को देश की आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाने के लिए विशेष योजनाओं का भी ऐलान किया। 12 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए 5 स्कॉम के साथ 1 करोड़ युवाओं को इंटरशिप की व्यवस्था, 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को 3 स्कॉम, आयकर के छूट स्लेब को बढ़ाकर मध्यम वर्ग और कर्मचारी वर्ग को बड़ी राहत, कृषि व उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान, मुद्रा लोन योजना 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई, स्वास्थ्य के लिए 100 करोड़ का लोन प्रावधान, किसानों और उनकी जमीनों को मिलेगा।

सर्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य सामग्री का अवैध परिवहन करने पर वाहन राजसात

सर्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य सामग्री का अवैध परिवहन करने पर वाहन राजसात

गरियाबंद (समय दर्शन)। सर्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य पदार्थों चावल व चने का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर एक वाहन को राजसात किया गया है। शासकीय खाद्यान्न सामग्रियों के अवैध परिवहन की शिकायत के संबंध में मामलों की जांच एवं परीक्षण कर अपर कलेक्टर द्वारा उक्त वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की गई है। इलेक्ट्रिकीय है कि शासकीय राशन के अवैध परिवहन के संबंध में छ.ग.सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज प्रकरण में आदेश पारित किया गया है। इसके तहत सर्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य पदार्थों चावल व चने का अवैध परिवहन किये जाने पर वाहन क्रमांक सीजी 04 जे.ए. 4727 को राजसात किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन को नीलाम करते हुए प्राप्त राशि शासन के पक्ष में जमा किया किये जाने हेतु आदेशित भी किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि शासकीय राशन सामग्री के अवैध परिवहन की शिकायत पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(क) में प्रदत्त अधिकारों के तहत छोग 0 सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के उल्लंघन किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7(1)(ग) के तहत जप्तशुदा वाहन को शासन के पक्ष में राजसात किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा प्रदान करके, बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस बना रहा है छत्तीसगढ़ के किसानों को सशक्त

भिलाई। भारत की प्रमुख प्राइवेट जनरल इश्योरेंस कंपनी, बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस, छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ 2024 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसलों के लिए बीमा को सुविधा प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, कोरिया, सारांगढ़-बिलासगढ़, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, कांकेर, सक्ती, मोहला - मानपुर - अम्बगढ़ चौकी सहित कई जिलों में कवरेज प्रदान की जा रही है। इसके तहत धान (सिंचाई और गैर-सिंचाई वाला), मक्का, काला चना, अरहर दाल, हरी मूंग दाल, मूंगफली, सोयाबीन, कोदो, कूटकी और रागी जैसे विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए व्यापक बीमा प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, उनके नुकसानों को कम करना और कृषि क्षेत्र में नई पद्धतियों को बढ़ावा देना है। पीएमएफबीवाई स्कीम के माध्यम से, बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस का लक्ष्य, किसी भी अप्रत्याशित प्राकृतिक घटना के कारण फसल को होने वाले नुकसान के लिए किसानों को आर्थिक सहायता और कवरेज प्रदान करना है। योजना के लाभों में तृण, बाढ़, सूखा और कोट हमले जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज को होने वाले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति देना शामिल है। अगर खराब मौसम के कारण बुआई नहीं हो पाती है, तो पॉलिसी इसके लिए बीमा राशि के 25% तक कवरेज प्रदान करती है। कटाई के बाद हुए नुकसान को भी इस फसल बीमा ऑफर के तहत कवर किया जाता है। इसके साथ ही, यह पॉलिसी स्थानीय आपदाओं, जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग और बिजली के कारण खेतों को हुए नुकसान को भी कवर करती है। किसान लोटेस्ट आंधर कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि और फसल बुआई से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रदान करके आसानी से फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

कलेक्टर अग्रवाल ने जिले में 34 नये आंगनबाड़ी भवनों की दी स्वीकृति

वर्नाचल क्षेत्रों में नये भवन बनने से बच्चों को पढ़ाई में होगी सहूलियत

गरियाबंद (समय दर्शन)। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जिले के दूरस्थ एवं वर्नाचल क्षेत्रों के गांवों में आंगनबाड़ी भवनों की समस्या को दूर करने 34 नये आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से 17 भवनविहीन एवं 17 अति जर्जर भवनों के बदले स्वीकृति की गई है। नये आंगनबाड़ी भवन बनने से छोटे बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास तथा पढ़ाई-लिखाई में भी सहायक होगी। साथ ही भवनों की समस्याओं से भी निजात मिल सकेगा। इलेक्ट्रिकीय है कि कुछ समय पूर्व कुछ गांव के ग्रामीणों ने गांव में नये आंगनबाड़ी भवन एवं जर्जर भवनों के बदले नये निर्माण की मांग को जिला प्रशासन को



अवगत कराया था। छोटे बच्चों के भविष्य एवं पढ़ाई-लिखाई को बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री अग्रवाल ने मामले को संज्ञान में लेते हुए नये भवनों की स्वीकृति दी है। साथ ही

महिला एवं बाल विकास विभाग एवं 15वें वित्त आयोग के समन्वय से निर्मित किया जायेगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि नये आंगनबाड़ी भवनों के लिए प्रदान 11 लाख 69 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि में से मनरेगा अभिसरण से 8 लाख रुपये, महिला एवं बाल विकास विभाग से 2 लाख रुपये एवं 15वें वित्त आयोग या अन्य मद से 1 लाख 69 हजार रुपये समन्वय किया गया है। उन्होंने बताया कि नये स्वीकृत भवनों में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई एवं खेलकूद तथा बौद्धिक-मानसिक विकास के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जायेगी। जिससे बच्चों को पढ़ाई का बेहतर माहौल मिलेगा। नये स्वीकृत भवनों में विकासखण्ड मैनुअल अंतर्गत प्रथम भूतबेड़ा, सासरपानी, ग्राम नवापारा के माहुलपारा, भैसमुड़ी, जाड़ापदर

कलेक्टर श्री अग्रवाल के निर्देशानुसार अधिक जलभराव वाले पुल-पुलियों में लगाया जा रहा सावधानी बोर्ड

पुल के ऊपर पानी रहने पर पार नहीं करने लोगों को किया जा रहा जागरूक

गरियाबंद (समय दर्शन)। पिछले कुछ दिनों से जिले में लगातार हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर है। साथ ही कई जगहों पर बारिश का पानी सड़कों और पुल-पुलियों के उपर से भी बहने की सूचना मिल रही है। ऐसे में कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने लोगों को भारी बारिश से सुरक्षित रखने एवं सावधानीपूर्वक पुल-पुलियों को पार करने के लिए जागरूक करने के निर्देश विभागीय अधिकारी को दिये हैं। कलेक्टर श्री अग्रवाल के निर्देशानुसार लोगों को सावधानीपूर्वक पुल-पुलियों को पार करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से पुल-पुलियों एवं सड़कों के किनारे सावधानी बोर्ड लगाया जा रहा है। इस कार्य में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एनएच एवं अन्य विभागों द्वारा समन्वय करके सावधानी बोर्ड लगाया



जा रहा है। जिले के मैदानी सहित दूरस्थ एवं वर्नाचल क्षेत्रों के पुल-पुलियों एवं सड़कों में भी सावधानी बरतने के सूचनायुक्त बैनर, प्लैक्स एवं स्थायी सूचना बोर्ड लगाया जा रहा है। इसके तहत जिले के दूरस्थ क्षेत्र में मैनपुर के कामेपुर रोड, अडुगड़ी नाला, राजापड़ाव से गौरगांव रोड, जरहीडीह नाला, धवलपुर से जरन्डीह, भाखड़ी पैरीनदी एवं गरियाबंद से उरुली, पारागांव नाला में सावधानी बोर्ड लगाकर लोगों को अधिक जलभराव से सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

विधानसभा का घेराव में पहुंचे कांग्रेसी, गरियाबंद शहर अध्यक्ष सहित कांग्रेस के पार्षद भी हुए शामिल



गरियाबंद (समय दर्शन)। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया गया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस का यह प्रदर्शन कई मायनों में काफ़ी अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने ब्लॉक, बूथ और वार्ड स्तर पर भी धीरे-धीरे जुटाने का लक्ष्य दिया था जिसमें नगर के कई कांग्रेस कार्यकर्ता व पार्षद शामिल हुए। इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस एकजुटता दिखाते हुए अपनी ताकत भी दिखाए जाते हैं कि बुधवार सुबह प्रदर्शन में शामिल होने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी

सचिन पायलट रायपुर पहुंच गए हैं। पायलट के प्रभारी बनने के बाद यह कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने गरियाबंद शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा घेराव के लिए गरियाबंद से सैकड़ों कार्यकर्ता रायपुर रवाना हुए। जिसमें प्रतिभा पटेल पार्षद, विमला साहू पार्षद, पार्षद ज्योति साहनी, अवध राम यादव अशोक जगत मुकेश रामटेके बाबा सोनी रिशेरा तांडी द्रवीण जगत स्वप्निल देव नागेश विजय सोनी सुभाष भैसल वासुदेव साहू नारायण सारथी ओमकार निपाद सचिन ध्रुव, शामिल रहे।

निगम राजस्व की टीम ने गुलाब का फूल देकर इंदिरा मार्केट के व्यापारियों को अस्थायी अतिक्रमण हटाने का किया आग्रह



दुर्ग (समय दर्शन)। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर का मुख्य मार्ग इंदिरा मार्केट पर व्यापारियों द्वारा अस्थायी रूप से अपनी दुकानों के बाहर सामग्री रखकर अतिक्रमण कर व्यापार कर रहे हैं। आवागमन सुलभ हो इसी उद्देश्य को लेकर अनूठी पहल करते हुये आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश एवं राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता के मार्गदर्शन में सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोहर के द्वारा टीम के साथ मुख्य बाजार इंदिरा मार्केट में व्यापारियों को गुलाब का फूल देकर आग्रह करते हुए सभी व्यापारियों से अपनी व्यवसाय सामग्री अपनी हदों में ही रखकर व्यापार करने हेतु कहा गया। ताकि राहगीरों तथा दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को कोई असुविधा न हो, ग्राहक अपने वाहन सड़क की लाईन के अन्दर रखकर सामग्री खरीदी कर सके तथा आवागमन में कोई बाधा भी उत्पन्न न हो। व्यापारियों के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण कर सड़क पर सामग्री रखने से सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। उन्होंने शहर के प्रति स्वच्छ रखने के लिए आग्रह पूर्वक सभी व्यापारियों से अलग अलग दुकानों में जाकर गुलाब का फूल देते हुए शहर के हित में तथा जीर्णोद्धार के सुगम आवागमन के लिए नगर निगम को सहयोग दिये जाने की अपील की। निगम एवं ट्राफिक व्यवस्था में सहयोग करने का वादा भी किया। आगामी त्योंहारों को दृष्टिगत रखते हुए व्यापारीगण निगम एवं ट्राफिक पुलिस प्रशासन को अपना पूरा सहयोग प्रदान करते हुए सड़क को बाधित नहीं करें ताकि आने वाले त्योंहारों की खरीदी ग्राहक आपकी दुकानों से खरीदी कर सकें। नगर निगम द्वारा आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश पर

अपने दुकान सीमा से बाहर निकाल कर व्यवसाय कर रहे व्यापारियों को फूल देकर अपने सीमा क्षेत्र में ही व्यवसाय करने निवेदन किया गया। यदि व्यापारी नहीं माने तो ऐसी स्थिति में जेसीबी के माध्यम से हटाने की कार्यवाही की जाएगी। जिसमें होने वाले नुकसान की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित व्यापारी को ही होगी। आने वाले समय पर त्योंहार के सीजन को देखते हुए यह कार्यवाही की जा रही है। ताकि आम नागरिकों को मार्केटिंग करने में कोई परेशानी न हो। इंदिरा मार्केट, हटरी बाजार लाइन, स्टेशन रोड, चण्डी मंदिर लाइन, मान होटल लाईन, लुचकी तालाब लाईन इन क्षेत्रों के सभी व्यापारियों को समझाई दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

साक्षरता की दिलाई गई शपथ

धमतर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अनुशंसित उल्लस नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को शत-प्रतिशत साक्षर करने का लक्ष्य है। डाईट नगरी के प्राचर्य ने बताया कि इसे हाइटेक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास, सतत शिक्षा हेतु डाईट नगरी में अध्ययनरत शिक्षार्थियों को साक्षरता शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर डाईट नगरी के अकादमिक संकाय, कार्यालयीन सदस्य एवं द्वितीय वर्ष के शिक्षार्थी उपस्थित रहे।

शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल को किया गया राजसात, कलेक्टर ने की कार्यवाही

गरियाबंद (समय दर्शन)। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जिले में शराब के अवैध निर्माण, भण्डारण एवं परिवहन पर सख्त रुख अपनाते हुए अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलों को राजसात करने की कार्यवाही की है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जप्तशुदा वाहनों की नीलामी के लिए सूचित किया गया है। उक्त वाहनों की नीलामी पश्चात प्राप्त धनराशि शासकीय खजाने में जमा की जायेगी। कलेक्टर ने कलेक्टर न्यायालय में दर्ज दो प्रकरणों की

सुनवाई के तहत अंतिम फैसला देते हुए शराब परिवहन में शामिल दो मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 06 जी.सी. 4810 एवं सीजी 15 डी 2206 को राजसात किया गया है। इलेक्ट्रिकीय है कि 13 जुलाई 2023 को मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 06 जी.सी. 4810 में प्लास्टिक बोरी में 18 नगर देशी मदिरा प्लेन तथा 14 नगर देशी मदिरा मसाला कुल मात्रा 5.7 बल्क लीटर रखकर अवैध परिवहन करने हुए पाया गया। इसी प्रकार 30 दिसम्बर 2023 को मोटरसाइकिल

क्रमांक सीजी 15 डी 2206 में 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकिन में 8 लीटर कच्ची महुआ शराब रखकर अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाया गया। उक्त दोनों प्रकरणों में वाहन को जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार किया गया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के तहत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत अवैध रूप से शराब परिवहन में प्रयुक्त दोनों वाहनों की राजसात की कार्यवाही की गई।

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग

मामला क्रमांक/ /अ-27/23-24
ईशतहार
(धारा 178 प्रारूप ख)

क्योंकि मौजा पोटीया कला तहसील व जिला दुर्ग के सहभूमिस्वामी लालू किसुन यादव आ. किशोरी प्रसाद यादव निवासी मीनाक्षी नगर बोर्ससी तहसील जिला दुर्ग ने निम्नांकित अनुसूची में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिये आवेदन किया है। एवं क्योंकि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है, एवं सुनवाई का दिनांक 13/8/24 स्थान तहसील दुर्ग पर दिन 11.00 बजे नियत किया गया है, उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हो, एवं अपनी आक्षेपों, यदि कोई हो, तो पेश करें।

उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नहीं कर पाने की स्थिति में किसी आक्षेप पर विचार नहीं किया जायेगा। (खाते का विवरण) सर्वेक्षण संख्यांक भू-खंडांक 174/50 क्षेत्रफल 0.0140 है. भू-राजस्व 0.05 पैसा आज दिनांक 19/7/24 प को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

तहसीलदार दुर्ग (छ. ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग, जिला दुर्ग

//उद्घोषणा//
रा0प्र0क0 2024061033000008 / अ-74/वर्ष 2023-24

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रा.प्र.कं. 2024061033000008 आवेदिका श्रीमती दिव्या साहू पति हरिश कुमार साहू निवासी ग्राम भोथली, तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम भोथली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1104/1 रकबा 0.160 हे. भूमि जो कि आवेदक के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है, आवेदक को पूर्व में मुल ऋण पुस्तिका प्राप्त हुआ था जो कही गुप्त हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 30/07/2024 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अधिकारता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयवधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16/06/2024 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
जारी दिनांक- 13/06/2024
सुनवाई दिनांक- 30/07/2024

अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग

मामले की श्रेणी: राजस्व
संदर्भ :- जिला- दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न.- 00018 वधेरा ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक- ऋ202324430107000064

ईशतहार
तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00018 के अंतर्गत ग्राम वधेरा के वर्तमान भूमिस्वामी पिताम्बर पिता/पति-पितामनबोध पता-वधेरा के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 295/21(0.0120) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता सुशील निर्मलकर पिता/पति-स्व. पिताम्बर पता-वार्डक्रं.- 55 बधेरा, दुर्ग, श्रीमती पुनम निर्मलकर, श्रीमती पूजा निर्मलकर पिता/पति-स्व. पिताम्बर पता-वार्डक्रं.- 55 बधेरा, दुर्ग के नाम पर पंजीयन/पंजी होने के उपरान्त नामांतरण / अभिलेख डुरुस्ती / खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 25/07/2024 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय न्यायालयतहसीलदारदुर्ग पर की जावेगी। उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो इशतहार प्रकाशन उपरान्त प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं / अधिवक्ता / आममुख्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 02/07/2024 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार दुर्ग (छ. ग.)

प्रसव पश्चात मरीजों के टांके खुलने की शिकायत- विधायक गजेंद्र यादव ने विस में उठाया सवाल

दुर्ग (समय दर्शन)। मानसून सत्र के तीसरे दिन दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने विधानसभा के सदन में बड़ा सवाल उठाया। महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को उजागर करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अमले की लापरवाही को सदन के पटल पर रखते हुए सरकार का ध्यान आकर्षण कराए। प्रसव पश्चात महिला मरीजों के टांके खुलने की लगातार शिकायत प्राप्त होने पर विधायक गजेंद्र यादव ने मामले को संज्ञान में लिया और सदन पर सवाल

पूछकर सम्बंधित मंत्री से जवाब मांगे। विधायक श्री यादव ने आज के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 2 वर्षों में कितने प्रसव सर्जरी से किये गये हैं ? व कितने मरीजों के टांके खुलने की शिकायत पर पुनः भर्ती हुए ? इसके क्या कारण रहे तथा क्या कार्यवाही की गई ? का सवाल उठाकर जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने सदन में सरकार से आग्रह किये। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम



विधानसभा 24 जुलाई 2024, मानसून सत्र, प्रश्नकाल, तीसरा दिन 24 जुलाई 2024

बिहारी जायसवाल ने दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव द्वारा उठाये गये सवाल का सदन में जवाब देते हुए बताया कि दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 02 वर्षों में कुल 6214 प्रसव सर्जरी से किये गये हैं व 16 मरीजों टांके खुलने की शिकायत पर पुनः भर्ती हुए। टांके खुलने के मुख्य कारण प्रसव पश्चात् रोगी के द्वारा स्वच्छता का ध्यान न रखना, उचित आहार पोषण न लेना एवं ओबेसिटी है। प्रसव पश्चात् प्रसूता महिलाओं की स्वच्छता एवं पोषण विषय पर

काउंसलिंग किया गया तथा टांके खुलने की शिकायत वाले मरीजों का उपचार किया गया। गौरतलब है विधायक गजेंद्र यादव अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी शासकीय अस्पतालों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक लेते रहते हैं। बीते दिनों हमर क्लिनिक और जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों का विजिट कर अस्पताल के चिकित्सकीय स्टाफ और मरीजों से ईलाज से संबंधित जानकारी लिए।

संक्षिप्त-खबर

बंसुला स्कूल में मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव एवम् शिक्षा सप्ताह



शासन के आदेश अनुसार प्राथमिक शाला बंसुला में गुरु पूर्णिमा उत्सव एवं शिक्षा सप्ताह का कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में सौरभ अग्रवाल जिलाध्यक्ष विश्व हिन्दू परिषद एवं संकुल समन्वयक गोवर्धन डडसेना उपस्थित थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात् पुष्पांजलि मैडम के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गयी। पूजन व वंदना पश्चात् अतिथियों का स्वागत किया गया। शाला विकास समिति के अध्यक्ष चमेली सागर, समिति के उपाध्यक्ष भारत साव के द्वारा अतिथियों का शाला श्रीफल एवं गमछा भेंटकर सम्मानित किया गया, साथ ही बच्चों के द्वारा विद्यालय के सभी शिक्षकों को पेन एवं श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। समिति अध्यक्ष चमेली सागर के द्वारा सभी शिक्षकों को श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सौरभ अग्रवाल ने गुरु की महत्ता के बारे में बच्चों को बताया और उन्होंने अपने माता पिता और गुरु का सदैव सम्मान करने की प्रेरणा दिए। समन्वयक डडसेना ने शिक्षकों का सम्मान करते हुए उनके आदेशों का पालन करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। शिक्षा सप्ताह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जिसमें अनीता मैडम एवं सीता मैडम द्वारा बनाया गया टी एम एम का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय के प्रधान पाठक प्रवीर कुमार बेहरा के द्वारा किया गया।

एनएमडीसी किरंदुल परियोजना ने पेश की मानवता की नायाब मिसाल



किरंदुल (समय दर्शन)। एनएमडीसी, किरंदुल परियोजना ने मंगलवार को 179 आपदा पीड़ित प्रत्येक परिवार को 20000/- रुपये चेक के माध्यम से मंगल भवन, बंगाली केम्प में आपदा सहयोग राशि ताबडतोड प्रदान कर मानवता की नायाब मिसाल कायम की है। एनएमडीसी लिमिटेड के सीएमडी अमिताभ मुखर्जी तथा निदेशकों के सतत मार्गदर्शन एवं कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन, दत्तेवाड़ा की सहमति एवं असीम सहयोग और मुख्य महाप्रबंधक तथा परियोजना प्रमुख, किरंदुल कॉम्प्लेक्स संजीव साहू के नेतृत्व में उक्त राशि के चेक सर्वश्री आर. राजाकुमार, महाप्रबंधक (उत्पादन), उपमहाप्रबंधक (कार्मिक) वी के माधव, सुब्रमण्यम एम्., महाप्रबंधक (विद्युत), संजय कोचर, महाप्रबंधक (खनन), विवेक चंद्रा, एसडीएम के कर कमलों से पीड़ित परिवारों को वितरित किए गए 7 परिवारों के नुकसान का सर्वे पटवारी एवं किरंदुल कॉम्प्लेक्स द्वारा गठित समिति ने किया। इसके पश्चात नुकसान का जायजा

सभी वर्ग के हित की चिंता करने वाला बजट- भाजपा

बसना (समय दर्शन)। देश ने भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया है। बसना विधानसभा संयोजक डॉ. एन. के. अग्रवाल ने कहा कि, केंद्र सरकार का यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा महिलाओं के सर्वतोमुखी विकास का एक नया अध्याय लिखेगा। भाजपा के स्थानीय प्रमुखों ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं के रोजगार और कौशल उन्नयन एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और नए रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ केंद्र सरकार ने युवा प्रतिभाओं की पूरी चिंता की है।



सिंचाई के लिए 11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए 109 फसलों पर फोकस करने के साथ-साथ दलहन, तिलहन और सब्जी की पैदावार पर नई घोषणाएं करके अन्नदाताओं की खुशहाली का पक्का इंतेजाम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है।

बसना नगर पंचायत के उपाध्यक्ष व भाजपा नेता सुमित अग्रवाल ने कहा कि, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत का संकल्प केंद्र सरकार की आदिवासियों के उत्थान की प्रतिवद्धता को व्यक्त करता है, जिससे देशभर के 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे। गरीबी के लिए जहां मुफ्त राशन योजना जारी रखने की घोषणा की गई है, वहीं महिलाओं के उत्थान और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान कर के केंद्र सरकार ने

मातृ शक्ति का वंदन किया है। देश के विकास के लिए लघु और मध्यम उद्योगों के लिए किए गए प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प पूर्ण होगा। 3 करोड़ नए पीएम आवास और मजदूरों के लिए नई हाऊसिंग स्कीम की घोषणाओं के साथ ही केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, बाढ़ व जलभराव नियंत्रण जैसे विषयों को भी बजट में शामिल कर समूचे देश के गांवों से लेकर बड़े शहरों तक की चिंता की है। भाजपा मण्डल अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि, टीडीएस के नियमों को सरल करने, आयकर में टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन में की गई बढ़ोत्तरी का स्वागत किया और कहा कि अमृतकाल का यह बजट हर मायने में संतुलित और महत्वपूर्ण है।

गुण्डे-बदमाशों व आपराधिक घटनाओं पर नजर रखना

- अब होगा आसान, पुलिस ने बनाया नया सर्विलांस प्लान
- अपराध रोकने व सड़क में जाम की स्थिति से निपटने सर्विलांस बनेगी मददकारी-एसपी शुक्ला



गतिविधियों पर खुफिया नजर रखेगी। इस सर्विलांस सिस्टम का कंट्रोल रूम कोतवाली पुलिस थाना सेक्टर-6 भिलाई को बनाया जाएगा। जहां बड़े टीवी स्क्रीन लगाने की तैयारी चल रही है। इन टीवी स्क्रीनों में सर्विलांस प्लान के लिए चिन्हित मार्गों की तस्वीरें दिखाई देती रहेंगी। जिससे आपराधिक घटनाओं के अलावा सड़क दुर्घटनाओं व सड़क पर जाम की स्थिति से निपटने यह नया सर्विलांस प्लान पुलिस के लिए मददगार साबित होगा। इस

जिला पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने सोमवार को छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के दुर्ग जिला इकाई द्वारा आयोजित चेम्बर सम्मेलन में जिलेभर के व्यापारियों के बीच साझा की। जिला पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने व्यापारियों के सभा में कहा कि दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण जिला है। जनता व व्यापारियों की सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा को लेकर मापदंड होने चाहिए, लेकिन वह नहीं हो पाया है। सुरक्षा के लिहाज से हम अभी भी पीछे चल रहे हैं। दुर्ग-भिलाई के करीब 20 लाख आबादी के पीछे 500 पुलिस जवानों की जिम्मेदारी है। जो बहुत कम है। जनता और व्यापारियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने जिला पुलिस द्वारा नया सर्विलांस प्लान तैयार किया गया है। जिसके आगामी दिनों में अच्छे परिणाम सामने आएंगे। नए सर्विलांस प्लान में जनता व व्यापारियों की भूमिका अहम होगी।

गरीब, किसान, युवा एवं महिलाओं की समृद्धि और विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट- भावना बोहरा



कवर्धा (समय दर्शन)। लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को प्रस्तुत किया गया। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को समर्पित यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। पंडरिया विधायक भावना ने कहा कि यह बजट देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर तेजी से ले जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भारत को निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर रखते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्तुत बजट 2024-2025 एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला को और सुदृढ़ करने वाला है, जो गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग और अन्य जरूरतमंद समूहों के सशक्तिकरण की दिशा के अत्यंत प्रभावी होगा। विधायक भावना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में यह बजट समावेशी, सर्वस्पर्शी और हर वर्ग को लाभान्वित करने वाला है। पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाते हुए, मोदी सरकार का यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को और गति देने के साथ आजादी के 100वें वर्ष तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रभावी बजट है। मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में भारत ने खुद को विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिस्थापित किया है। इस बजट से भारत की विकास यात्रा को और बल मिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार समाज के अतिम वृद्धि के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु निरन्तर कार्यरत है, जिसकी झलक हमें इस बजट में देखने को मिलती है। यह आम बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाओं हेतु 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है। जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, जनजातीय-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों के लिए प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी जिससे 63,000 गांव शामिल होंगे जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत लोगों को 10 लाख रुपये तक का लोन देने की सुविधा थी। लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है लघु और कुटीर उद्योग के लिए 100 करोड़ रुपये तक का लोन देने की घोषणा, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ग्रामीण अवसरंचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसके साथ ही रक्षा, अनुसंधान, उर्जा, मानव संसाधन, कृषि जैसे सभी क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। भावना बोहरा ने कहा कि रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के पैकेज की घोषणा की गई, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5,000 रुपये प्रति माह इंटरशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी।

दुर्ग (समय दर्शन)। गुण्डे-बदमाशों, चोरों व आपराधिक घटनाओं पर नजर रखना और चौक-चौराहों पर भीड़ को नियंत्रित करना अब पुलिस के लिए आसान होगा। इसे मूर्तरूप देने जिला पुलिस द्वारा नया सर्विलांस प्लान तैयार किया गया है। आधुनिक तकनीक से लैस प्लान के प्रथम चरण में यह सर्विलांस कुम्हारी से अंजोरा और जेवरा सिरसा से पुलगांव चौक तक के सड़क एरिया को कवर करेगा। इन मार्गों के चौक-चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जो कैमरे सड़क पर होने वाली हर

नए सर्विलांस प्लान की एक खास बात होगी कि इसमें एक साफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। जिसमें हिस्ट्रीशीटर गुण्डे-बदमाशों के फोटो अपलोड किए जाएंगे। कोई भी हिस्ट्रीशीटर उक्त मार्ग से गुजरेगा तो कैमरे के जद में आने से कंट्रोल रूम में टीवी स्क्रीन में पुलिस को उसके आवाजाही के संकेत मिलेंगे। नए सर्विलांस प्लान की तैयारी चल रही है। 5 से 6 माह में यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। नए सर्विलांस प्लान की यह जानकारी

केन्द्रीय बजट विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी - विजय शर्मा

कवर्धा (समय दर्शन)। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 2024-25 के प्रस्तुत बजट को विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे देश सहित प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल



आपूर्ति और र व च छ त। परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों की भी सराहा। उन्होंने कहा कि नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। 5 साल में 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़

उन्नत बनेगा। उन्होंने कहा कि शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए गए कोष से नई खोजों और आविष्कारों को बल मिलेगा। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान युवा पर बजट में फोकस किया गया है। यह बजट देश सहित प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सभी क्षेत्रों में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देगा।

थाना बसना पुलिस एवम् साइबर टीम की संयुक्त कार्यवाही

- थाना बसना क्षेत्र में महेन्द्रा जायो 3200 से सिगरेट पान मसाला के चोरी में एक आरोपी गिरफ्तार



पुलिस टीम के द्वारा संदेही वाहनों की चेकिंग किया जा रहा था, उसी दौरान थाना बसना क्षेत्र के वाहन महेन्द्रा जायो 3200 से अज्ञात चोर द्वारा सिगरेट पान मसाला

चोरी द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मुखबोर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सीटी ग्राउण्ड बसना के पास एक सफेद रंग की कार में चोरी का सिगरेट रखकर बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि, सूचना पर थाना बसना पुलिस द्वारा आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे नाम पता पछुने पर अपना नाम (01) मिथलेश सोनी पिता स्व0 लक्ष्मीप्रसाद सोनी उम्र 38 साल साकिन हाऊसिंग बोर्ड कोलानी चंदखुरी रायपुर छग0 का रहने वाला बताया। जिसके कब्जे से दो पुडिया लिबर्टी सिगरेट

व एक पुडिया टोटल मिंट सिगरेट को बरामद किया गया। जिसे पुछताछ करने पर अपने और दो अन्य साथियों के साथ और भी अन्य जगहों से चोरी करना बताया। आरोपी के विरुद्ध थाना बसना में अपराध धारा के तहत कार्यवाही किया गया। फार आरोपी को पता सजी की जा रही है।

बरामद मशरूका

01:- चोरी हुआ सिगरेट व टोटल मिंट सिगरेट कीमती 4960 रुपये बरामद 02 एक सफेद रंग की कार* संपूर्ण कार्यवाही थाना बसना महासमुंद पुलिस के द्वारा किया गया है।